

● वर्ष-6
● अंक-59
रायपुर, गुरुवार
08 अक्टूबर 2026
● पृष्ठ-8
मूल्य-३ रु.

॥ संगछध्वम् संवदध्वम् ॥

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>> सेवा संकल्प अभियान के तहत ...

प्रीएम मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष देश के विकास और परिवर्तन की प्रेरक यात्रा : मुख्यमंत्री

प्रदेश के 38 स्थानों पर बनेंगे ‘सेवा ज्योति संकल्प चौक’ : साय

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में शासन प्रमुख के रूप में जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज राजधानी रायपुर में सेवा, संकल्प और राष्ट्र निर्माण की भावना से ओतप्रोत ‘विकसित भारत संकल्प सभा’ एवं ‘सेवा ज्योति यात्रा’ का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के जिला मुख्यालयों सहित कुल 38 स्थानों पर ‘सेवा ज्योति संकल्प चौक’ के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने राजधानी रायपुर के तेलीबांधा चौक को भी ‘सेवा ज्योति संकल्प चौक’ के रूप में विकसित करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ये संकल्प चौक जनसेवा, राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत के संकल्प के प्रतीक बनेंगे। ये आने वाली पीढ़ियों को यह प्रेरणा देंगे कि राष्ट्र की प्रगति में प्रत्येक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और नगरिकों को विकसित भारत एवं विकसित



छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प दिलाया। इसके पश्चात उन्होंने हाथों में मशाल लेकर ‘सेवा ज्योति यात्रा’ का नेतृत्व किया और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से प्रारंभ हुई यह यात्रा तेलीबांधा चौक तक निकाली गई। बड़ी संख्या में नागरिकों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक यात्रा में सहभागिता की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके निरंतर सेवाकाल के आज 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन 25 वर्षों की यात्रा जनसेवा, सुशासन, विकास और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण की यात्रा है।

वैश्विक अवसरों से जुड़ रहा छग

अपने हालिया सिंगापुर प्रवास का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की सोच है कि भारत के राज्य भी दुनिया के विभिन्न देशों के साथ अपने आर्थिक और संस्थागत संबंधों को मजबूत करें तथा निवेश, तकनीक, कोशल और नवाचार के वैश्विक अवसरों का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि इसी दिशा में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ और हरियाणा को सिंगापुर में आयोजित प्रथम सिंगापुर-भारत विकास नेटवर्क फोरम-2026 में भागीदारी के लिए चुना गया। सिंगापुर प्रवास के दौरान उद्योग जगत, निवेशकों और बिजनेस फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और साझेदारी को लेकर सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और सिंगापुर के संबंध पुराने और मजबूत हैं। सिंगापुर में विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति वैश्विक विश्वास तेजी से बढ़ा है। आज दुनिया भरत की विश्वास, संभावनाओं और विकास के बड़े केंद्र के रूप में देख रही है।

छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मिलता है भरपूर सहयोग

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने से पहले विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के अनेक क्षेत्रों का व्यापक भ्रमण किया था। इस कारण वे प्रदेश की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के साथ यहां की संभावनाओं से भी भली-भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री श्री मोदी से छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा होती है, प्रदेश को अपेक्षा से बढ़कर उनका सहयोग और मार्गदर्शन मिलता है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ विकास के नए अवसरों से जुड़ रहा है और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका को लगातार मजबूत कर रहा है।

शिक्षा के अधिकार सीटों का ब्योरा सही नहीं देने पर हाईकोर्ट नाराज, सरकार को दिया अवसर

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों और उनमें प्रवेश से संबंधित सही रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है. चीफ जस्टिस के. आर. महापात्रा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की स्पेशल डिवीजन बेंच ने राज्य शासन को सभी स्कूलों में आरटीई के तहत आरक्षित सीटों और बच्चों से संबंधित सही एवं पूर्ण रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 18 नवम्बर को होगी।

मामला भावत की ओर से दायर जनहित याचिका से जुड़ा है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता देवर्षि ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि शासन द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड में कई बड़े स्कूलों में आरटीई के तहत आरक्षित सीटों की संख्या शून्य या बेहद कम बताई गई है. रिकॉर्ड की वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाने के कारण शासन द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर सवाल उठाए गए. मामले की सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच



ने शासन द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट के साथ इस तरह मजाक नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि पूर्व में वर्ष 2016 में दिए गए आदेशों के बावजूद उनका उचित अनुपालन नहीं हुआ है.

कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया कि सभी स्कूलों का सही और सत्यापित रिकॉर्ड अगली सुनवाई में पेश किया जाए, यदि 18 नवंबर तक सभी स्कूलों का सही डेटा पेश नहीं किया गया, तो शिक्षा सचिव कमलप्रीत सिंह के खिलाफ धारा 311 के तहत कार्रवाई की जाएगी. हाईकोर्ट ने 18 नवंबर तक का समय देते हुए इसे रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर बताया है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अर्जी पर विचार करने के लिए सहमति जताई। इस अर्जी में 23 सितंबर के उस बंटे हुए फ़ैसले को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसमें यह तय होना था कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसीएस) की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए या नहीं। इससे पहले का फ़ैसला तब आया था जब सरकार ने 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी संविधान पीठ के पास भेजने का अनुरोध किया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की दो जजों की बेंच ने इस बात पर अलग-अलग राय दी थी कि क्या ऐसा मामला बड़ी बेंच को भेजना ज़रूरी है या नहीं। जस्टिस दत्ता का मानना ​​था कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है,



जबकि जस्टिस शर्मा चाहते थे कि पाँच जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस पर विचार करे। विचारों में अंतर को देखते हुए, बेंच ने निर्देश दिया कि मामले को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के सामने रखा जाए ताकि सही संख्या वाली बेंच का गठन किया जा सके। इसी बंटे हुए फ़ैसले के बाद, बुधवार को सीजेआई सूर्य कांत के सामने फ़ैसले को वापस लेने (रि कॉल) की अर्जी का ज़ि़क़्र किया गया। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने सीजेआई और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और

वी. मोहना के सामने यह अर्जी रखी और बेंच को बताया कि इस याचिका में 23 सितंबर के फ़ैसले को वापस लेने की मांग की गई है। संकरनारायणन ने कहा मुख्य चुनाव आयुक्त के मामले में बंटा हुआ फ़ैसला आया है। हमने फ़ैसले को वापस लेने के लिए एक अर्जी दी है। छट्ठड़ सूर्यकांत ने कहा कि अदालत इस अर्जी पर फ़ैसला लेने से पहले उसकी जांच करेगी। उन्होंने कहा हम जांच करेंगे और फिर कोई फ़ैसला लेंगे। शंकरनारायणन ने साफ़ किया कि यह एप्लीकेशन एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन (आईए) थी, जिसमें जस्टिस दत्ता और जस्टिस शर्मा के 23 सितंबर के फ़ैसले को वापस लेने की मांग की गई थी। ध्यान दें कि ढ़ू एक औपचारिक एप्लीकेशन होती है जो किसी केस के चलने के दौरान कोर्ट से कोई खास आदेश या निर्देश पाने के लिए दायर की जाती है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

बैलेट पेपर से हुए चुनावों में भाजपा ने 42 में से 32 सीटें जीतीं

नई दिल्ली। भारतीय चुनावी राजनीति में इन दिनों इन्वीएम बनाम बैलेट पेपर की बहस फिर तेज है। विपक्षी दलों का एक वर्ग लगातार मांग कर रहा है कि देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जगह पुराने बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। असम के सिलचर में 3 अक्टूबर को नगर निगम के पहले चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान हुआ। परिणाम में भाजपा ने 42 में से 32 सीटें जीतीं और उसकी भाजयोगी असम गण परिषद ने दो सीटें हासिल कीं। कांग्रेस को केवल दो सीटें मिलीं, जबकि छह सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। यानी बैलेट पेपर वाले चुनाव में भी भाजपा-नीत एनडीए ने दो-तिहाई से अधिक सीटें जीत लीं। यह परिणाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्वीएम पर सवाल उठाने वाली राजनीति में अक्सर यह धारणा बनाई जाती है कि यदि चुनाव बैलेट पेपर से हो तो परिणाम अलग होगा। सिलचर का परिणाम कम-से-कम इतना ज़रूर बताता है कि बैलेट पेपर अपने आप किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में परिणाम नहीं बदल देता। मतदाता जिस राजनीतिक दल को समर्थन देना चाहता है, वह अपना समर्थन मतदान की किसी भी व्यवस्था में व्यक्त कर सकता है।

शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग के फैसले को सही ठहराया

नयी दिल्ली। सात अक्टूबर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में निर्वाचन आयोग के उस फैसले का बचाव किया, जिसमें उसे असली शिवसेना के रूप में मान्यता देते हुए पार्टी का चुनाव चिह्न ‘धनुष-बाण’ आवंटित किया गया था। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष

शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन. के. कौल ने कहा कि इस बात का “रस्ती भर भी सबूत नहीं” है कि 2011 के बाद शिवसेना का कोई संविधान निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। कौल ने पार्टी के संविधान, आंतरिक लोकतंत्र, निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र और चुनाव चिह्न विवाद के निपटारे के लिए आयोग द्वारा फैसला किए जाने के समय समेत कई मुद्दों पर दलील दीं। उन्होंने कहा कि आयोग ने अपने दो आदेशों में दर्ज किया था कि उसके पास उपलब्ध पार्टी का एकमात्र संविधान 2011 का था।

ऑल इंडिया और राज्य कोटे के आरक्षण में अंतर पर विवाद

रायपुर। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) कार्डसिलिंग 2026 में 455 अंक हासिल करने वाले परीक्षार्थी को ऑल इंडिया कोटे के माध्यम से प्रदेश के किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिल सकी, जबकि इसी अंक पर राज्य कोटे से रायपुर स्थित पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। इस स्थिति का मुख्य कारण ऑल इंडिया और राज्य कोटे के बीच आरक्षण नियमों का बड़ा अंतर होना है। ऑल इंडिया कोटे में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए केवल 12 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है, जबकि छत्तीसगढ़ में इस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 32 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू है। आरक्षण व्यवस्था में इसी अंतर के कारण राज्य कोटे में कम अंकों पर भी प्रतिष्ठित कॉलेजों में प्रवेश संभव हो पा रहा है। छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की कुल 3,025 सीटें हैं, जहां 15 सरकारी मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इन सरकारी संस्थाओं की 15 प्रतिशत सीटें ऑल इंडिया कोटे के लिए आरक्षित रखी जाती हैं, जिन पर नीट अंक और मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश दिया जाता है।

परिवार का अहंकार बोल रहा है राहुल पर बरसे सुधांशु त्रिवेदी

नई दिल्ली। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पहले परिवार ने दिल्ली की सड़कों पर जो किया, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। इससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि उन्हें संविधान से कोई लेना-देना नहीं है; उन्हें बस अराजकता से मतलब है। इसका सबूत इस बात से मिलता है कि जब चुनाव आयोग (ईसी) उनसे मिलने को तैयार था, तो वे भी उनसे मिलने को तैयार थे। संविधान कहता है कि ईसी, सीजेआई या सीएजी को किसी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में नहीं बुलाया जा सकता। राहुल पर हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि लेकिन वे (विपक्ष के नेता) कहते हैं कि उन्हें अपनी पार्टी के सांसदों के सामने पेश होना चाहिए। इसका मतलब है कि यह कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि अब उनके परिवार का अहंकार बोल रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूँ कि एस्पी उन्हें उत्तर प्रदेश में 50 सीटों के लायक समझती है।

माओवादियों का हथियार-विस्फोटक डंप पुलिस ने खोद निकाला

रायपुर। महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा से लगे कोपर्शी जंगल में माओवादियों द्वारा जमीन में छिपाकर रखा गया हथियार और विस्फोटक सामग्री का डंप गडचिरोली पुलिस ने बरामद किया है. सर्चिंग के दौरान पुलिस को .303 रायफल, दो सिंगल शॉट रायफल, दो देशी पिस्टल और एक बीजीएल लॉन्चर समेत 6 अग्निशस्त्र मिले. इसके अलावा 10 बीजीएल सेल, 21 ज़िंदा कारतूस, 7 डेटोनेटर और 150 मीटर केबल वायर भी जब्त की गई है. पुलिस को सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा के कोपर्शी जंगल में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करने और विस्फोट करने के लिए बड़ी मात्रा में हथियार व विस्फोटक जमीन में छिपाकर रखे हैं. सूचना के आधार पर 6 अक्टूबर को एस्पी एम. रमेश के मार्गदर्शन में विशेष अभियान चलाया गया. प्राणहिता की विशेष अभियान टीम की 5 टुकड़ियों और बीडीडीएस की 2 टीमें को सर्चिंग के लिए भेजा गया जवानों ने जंगल को घेरेकर संदिग्ध स्थानों की बारीकी से तलाशी ली. इस दौरान जमीन में छिपाकर रखा गया हथियार और विस्फोटक सामान बरामद हुआ।



राहुल देश को कर रहे अस्थिर : नितिन नवीन

नई दिल्ली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विपक्ष और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस देश के विपक्ष के नेता अराजकता के माहौल में असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं उनसे साफ़ तौर पर कहना चाहता हूँ कि भारत की जनता उनके मकसद और इरादे को कभी भी हकीकत नहीं बनने देगी। उन्होंने हमेशा उन लोगों की परवाह की है जो यहाँ की जनता के अधिकार छीनते हैं। वह असामाजिक तत्वों की मदद से दिल्ली में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

नितिन नवीन ने आगे कहा कि मैं विपक्ष के नेता से कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को अधिकार दिलाने की वह बात करते हैं, भारत की जनता ऐसे चुसपैठियों को कभी भी अधिकार नहीं देगी। आप किसकी परवाह करते हैं? आप किसके लिए लड़ रहे हैं? ...अगर स्क्रूक्रे के ज़रिए ऐसे चुसपैठियों के नाम हटा दिए जाते हैं और फिर भी आप इसे लेकर देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल आप पर ही उठता है। ऐसी अराजक सोच



का जवाब भारत की जनता देगी। इतिहासजानें

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बुधवार को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर के पास हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस के जवानों ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा को भी जंतर-मंतर के पास उस जगह से हटा दिया, जहाँ ढूढछड़ गठबंधन के सांसदों को विरोध-प्रदर्शन वाली जगह पर जाने से रोका गया था। अब पुलिस इन सांसदों को हिरासत में ले रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा ने कहा कि जो सांसद सिर्फ़ चुनाव आयुक्त से मिलना चाहते हैं, उनके साथ ये ऐसा बर्ताव करते हैं। हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता है। वे सांसदों को पीट रहे हैं। पुलिसवालों ने मुझे जगह-जगह खरोंच दिया है। उन्होंने हमें ज़मीन पर पटक दिया। अब हम यहाँ से नहीं हटेंगे।

हर एफआईआर मेरे लिए मेडल : राहुल गांधी

नई दिल्ली। जनपथ स्थित सागर रत्ना में लंच करने के बाद, विपक्षी सांसद सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करने के लिए बस से जंतर-मंतर की ओर बढ़े। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि जैसा कि मैंने कल कहा था, लगभग 300 सांसद मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि हम वहां



विरोध-प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसलिए, आज हमारा प्लान है कि हम विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगह, जंतर-मंतर जाएं और वहां एक साथ बैठकर देश को बताएं कि हमारे लिए ज्ञानेश कुमार देश के वैध चुनाव आयुक्त नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत और ज्ञानेश कुमार ने देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है। जैसा कि मैंने कल कहा था, जिन्होंने ऐसा किया है, वे देश के साथ गद्दारी करने वाले हैं और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ-ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा। जब उनसे उनके खिलाफ दर्ज सङ्कटके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ 45 एफआईआर दर्ज हैं। मेरा लक्ष्य 100 एफआईआर का है। मैं चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ 100 एफआईआर दर्ज हों। हर एफआईआर मेरे लिए एक मेडल की तरह है।



पिता-पुत्र पर चाकू से हमला करने वाले एक नाबालिग सहित पांच गिरफ्तार

धमतरी। पिता-पुत्र पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से नाबालिग को छोड़कर शेष चार आरोपियों का सिर मुड़वाकर पुलिस में सदर में जुलूस निकाला. बता दें कि दो रोज पूर्व मछली पकड़ने की जानकारी दीपर समाज के लोगो को देने की शंका में आरोपियों ने चाकू से पिता और उसके दो पुत्र पर हमला किया था. पुलिस ने जांच के बाद पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें रितेश कुमार ध्वव, आलेक रामटेके, राम साहू और चंद्रशेखर सहित एक नाबालिग शामिल हैं. सभी आरोपी दानी टोला के निवासी है. मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है.

पेट्रोल पंप फूंकने की कोशिश, दो बाइकों में भी लगाई आग

धमतरी। जिले के मगरलोड में आधी रात पेट्रोल पंप को आग के हवाले करने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना छट्टझड्डू केम्रे में कैद हुई है। फूटेज में एक संधिध पहले पेट्रोल पंप कर्मचारियों से गाली-गलौज करता नजर आ रहा है। इसके करीब दो घंटे बाद वह दोबारा पेट्रोल पंप पहुंचा और वहां खड़ी दो मोटरसाइकिलों में आग लगा दी। इसके बाद पेट्रोल पंप के नोजल में भी माचिस लगाने की कोशिश की गई। गनीमत रही कि आग पेट्रोल-डीजल तक नहीं पहुंची, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मामला मेधा स्थित माता रानी प्यूल्स का है। बताया जा रहा है कि रात करीब 1:30 बजे संधिध ने पेट्रोल पंप परिसर में खड़ी दो मोटरसाइकिलों में आग लगा दी।

समान नागरिक संहिता पर सरगुजा संभाग में होगी बैठक

अम्बिकापुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों तथा विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के लिए सरगुजा संभाग में दो दिवसीय बैठक आयोजित की जाएगी। समान नागरिक संहिता समिति के सचिव की ओर से जारी पत्र के अनुसार बैठक 8 अक्टूबर को अंबिकापुर और 9 अक्टूबर को जशपुर में होगी। पत्र के अनुसार 8 अक्टूबर को अंबिकापुर में शासकीय पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में दोपहर 3 बजे बैठक रखी गई है। इसमें सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर और कोरिया जिलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जशपुर में बैठक होगी, जिसमें जशपुर जिले के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सरगुजा संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने जिलों के राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों, शिक्षाविदों, प्रतिष्ठित नागरिकों, विशिष्ट नागरिकों, गणमान्य नागरिकों तथा निगम/मंडल/आयोग के प्रतिनिधियों को उपस्थित होने का अनुरोध किया है।

आरटीई सीटों का ब्योरा सही नहीं देने पर एचसी नाराज

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों और उनमें प्रवेश से संबंधित सही रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस के। आर। महापात्रा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की स्पेशल डिवीजन बेंच ने राज्य शासन को सभी स्कूलों में आरटीई के तहत आरक्षित सीटों और बच्चों से संबंधित सही एवं पूर्ण रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवम्बर को होगी। मामला भगवंत की ओर से दायर जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिकांश देवर्षि ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि शासन द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड में कई बड़े स्कूलों में आरटीई के तहत आरक्षित सीटों की संख्या शून्य या बेहद कम बताई गई है। रिकॉर्ड की वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाने के कारण शासन द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर सवाल उठाए गए। मामले की सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने शासन द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट के साथ इस तरह मजाक नहीं किया ।

जनसेवा से राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष के संकल्प के साथ जिले में निकली सेवा ज्योति यात्रा

एमसीबी। सेवा संकल्प अभियान के तहत मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में जिला स्तरीय ‘सेवा ज्योति यात्रा’ का आयोजन स्वामी आत्मानंद विद्यालय परिसर से किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा से राष्ट्रसेवा के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन से प्रेरणा लेते हुए सेवा, समर्पण, जनभागीदारी तथा विकसित भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों एवं नागरिकों ने सहभागिता की।

कार्यक्रम का शुभारंभ माता एवं छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर राष्ट्रीयगान के साथ किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा, भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह, बाबूलाल अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।



कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा से राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा के माध्यम से सेवा, समर्पण, जनभागीदारी और राष्ट्र निर्माण की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने

उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणजनों से सेवा की भावना के साथ आगे बढ़ते हुए विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से आभासी माध्यम से ‘विकसित भारत संकल्प सभा एवं सेवा ज्योति’ कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने जनसेवा के 25 वर्षों के सफर को देशवासियों के विश्वास, कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के सहयोग से जुड़ा बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से अब तक के सफर में उन्हें अनेक लोगों और घटनाओं से सीखने

का अवसर मिला। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि सफलता ने विनम्रता, कठिनाइयों ने संघर्ष और आलोचनाओं ने आत्ममंथन करना सिखाया। उन्होंने कहा कि हर संकट ने धैर्य की परीक्षा ली और हर उपलब्धि ने बड़े लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दिया। प्रधानमंत्री ने ‘सबका प्रयास’ को र्देशित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने देशवासियों के विश्वास और कार्यकर्ताओं के परिश्रम को अपनी शक्ति बताया तथा भारत के लोकतंत्र और संविधान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।

दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण शिविर जगदलपुर के लिए रवाना

विधायक आशाराम नेताम ने हरी झंडी दिखाकर बसों को किया रवाना, 277 दिव्यांग हितग्राहियों को मिलेगा लाभ

उत्तर बस्तर कांकेर। सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत कांकेर जिले के दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए आज न्यू बस स्टैंड स्थित डोम से दिव्यांग हितग्राहियों के 277 सदस्यीय दल को जगदलपुर के लिए रवाना किया गया। विधायक आशाराम नेताम, नगर पालिका अध्यक्ष अरुण कौशिक, कलेक्टर कुन्दन कुमार, जिला पंचायत सीईओ हरेश मण्डवी एवं महेश जैन ने हरी झंडी दिखाकर बस सहित 06 वाहनों को रवाना किया। विधायक नेताम और कलेक्टर कुन्दन कुमार ने वाहन में बैठे दिव्यांगजनों को पुष्प भेंटकर स्वस्थ जीवन एवं शुभ यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। जगदलपुर के क्रीड़ा परिसर धरमपुरा में आयोजित नि:शुल्क दिव्यांग शिविर में कांकेर जिले के 277 दिव्यांग हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। इनमें 97 हितग्राहियों को कृत्रिम अंग तथा 180 हितग्राहियों को विभिन्न सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। कृत्रिम हाथ 38, कृत्रिम पैर 59, बैसाखी 64, श्रवण यंत्र 55, छड़ी 43, कैलिसर्प 2, वॉकर 3, वॉकिंग स्टिक 5, चश्मा 6 एवं जूता सहित अन्य सहायक उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा हितग्राहियों को



जगदलपुर ले-जाने और वापस लाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की गई है। यात्रा के दौरान दिव्यांगजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए वाहनों में व्हीलचेयर सहित आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक वाहन में दिव्यांग हितग्राहियों की सहायता के लिए सहायक भी नियुक्त किए गए हैं। यात्रा के दौरान भोजन, पानी एवं आवश्यक सहयोग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, ताकि दिव्यांग हितग्राही आराम से शिविर स्थल तक पहुंच सकें। वाहन में चढ़ने-उतरने, व्हीलचेयर के उपयोग तथा अन्य जरूरतों के लिए भी सहयोगी कर्मचारी मौजूद रहेंगे। विधायक श्री आशाराम नेताम ने कहा कि दिव्यांगजनों की सेवा और उन्हें उनकी जरूरत के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन द्वारा इस तरह की पहल के माध्यम से दिव्यांगजनों को उनके गांव और जिले से बाहर जाकर सुविधा प्राप्त करने में सहयोग देना सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे, यही

सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य है। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों की सेवा का यह अवसर जिला प्रशासन के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि हितग्राहियों को शिविर तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए परिवहन से लेकर व्हीलचेयर, सहायक एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि संभव है कि कुछ पात्र दिव्यांगजन किसी कारणवश आज जगदलपुर जाने वाले दल में शामिल नहीं हो पाए हों। ऐसे दिव्यांगजन निराश न हों। 14-15 अक्टूबर को दूतेवाड़ा में आयोजित होने वाले शिविर में भी उन्हें लाभ लेने का अवसर मिलेगा। जिला प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी पात्र दिव्यांगजन शासन की सुविधा से वंचित न रहे। इसी प्रकार शिविर में चारामा से 45, नरहरपुर से 39, भानुप्रतापपुर से 38, कांकेर से 37, दुर्गुकोंदेल से 48, अंतागढ़ से 36 तथा कोयलीबेड़ा से 18 दिव्यांग हितग्राही शामिल होंगे। इसके अलावा नगर पंचायत अंतागढ़ से 6, नरहरपुर से 4 तथा पखांजूर से 6 हितग्राही भी लाभान्वित होंगे। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा दूरस्थ एवं संवेदनशील क्षेत्रों के दिव्यांगजनों को शासन की योजनाओं से जोड़ने तथा उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुरूप कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के अलग-अलग शहरों में बीजेपी के कई आयोजन

दुर्ग/सूरजपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में ‘सेवा संकल्प’ के तहत विशेष सभा का आयोजन किया गया। रविशंकर स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, आम नागरिक और छात्र-छात्राएं पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं और देशवासियों को वचुंअली संबोधित करते हुए 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन और इस दौरान सामने आई चुनौतियों का उल्लेख किया। सभा में प्रधानमंत्री के संबोधन को कार्यकर्ताओं ने सुना और उनके सेवा, संघर्ष और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के बाद बाइक रैली भी निकाली गई। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 8 अक्टूबर को दुर्ग पहुंचेंगे और यहीं से महतारी वंदन योजना की किस्त का बटन दबाकर हितग्राहियों के खतों में राशि जारी करेंगे। सेवा संकल्प अभियान के तहत हितग्राहियों को सामग्रियों का वितरण भी किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रंगोली का निरीक्षण करेंगे।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में आज 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर सूरजपुर के रंग मंच मैदान में आयोजन किया गया। इसमें गुजरात की सह प्रशासनी और विधायक गोमती साय शामिल हुईं। फरवरी 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। यहीं से सरकार के मुखिया के तौर पर उनके 25 वर्ष के सफर की शुरुआत हुई। सूरजपुर में सेवा ज्योति यात्रा के समापन अवसर पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गोमती साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक देश की सेवा में लंबा समय दिया है और यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। सेवा ज्योति यात्रा के सूरजपुर जिला मुख्यालय पहुंचने के बाद यात्रा का समापन किया गया।

अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग ने पकड़ा जोर, प्रदर्शन शुरु



कांकेर। अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग ने फिर जोर पकड़ लिया है। वर्षों पुरानी मांग को लेकर एक बार फिर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू हो गया है। आंदोलन के पहले दिन वीर नारायण सिंह चौक स्थित धरना स्थल पर क्षेत्रीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। इसी दौरान मासबरस ग्राम पंचायत की महिलाओं ने धरना स्थल पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया। अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर क्षेत्रवासी पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से आंदोलन और संघर्ष करते आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अंतागढ़ की भौगोलिक स्थिति

और क्षेत्र से शासन को मिलने वाले राजस्व को देखते हुए इसे पृथक जिला बनाया जाना चाहिए। आंदोलन को गति देने में स्थानीय युवाओं की भी अहम भूमिका रही है। युवाओं ने पिछले कुछ महीनों के दौरान अंतागढ़ क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों और साप्ताहिक बाजारों में हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस अभियान के जरिए लोगों से जिला बनाने की मांग के समर्थन में हस्ताक्षर कराए गए। धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग है। उन्होंने शासन-प्रशासन से इस दिशा में जल्द निर्णय लेने की मांग की।

10 वर्षीय हेजल ने जिला शिक्षा अधिकारी से किया संवाद

सक्ती। बच्चों में छिपी प्रतिभा को मंच प्रदान करने और उनमें आत्मविश्वास, संवाद-कौशल, नेतृत्व क्षमता तथा अभिव्यक्ति की कला विकसित करने की दिशा में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला धमनी, संकुल केंद्र हसीद (ब), विकासखंड जैजैपुर, जिला सक्ती (छत्तीसगढ़) की 10 वर्षीय छात्रा हेजल महंत ने एक सराहनीय एवं अभिनव पहल की। हेजल ने आज 5 अक्टूबर 2026 को जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती श्री विष्णु कुमार टांडे जी का शैक्षिक पॉडकास्ट साक्षात्कार लिया। इस पॉडकास्ट का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षा तक सीमित न रखते हुए उन्हें वास्तविक जीवन से जुड़े विषयों पर संवाद करने, प्रश्न पूछने, अपने विचार व्यक्त करने तथा प्रशासनिक एवं शैक्षिक क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तित्वों से सीखने का अवसर प्रदान करना है। इस पहल के माध्यम से बच्चों में संचार कौशल, डिजिटल साक्षरता, रचनात्मक सोच, जिज्ञासा, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का प्रयास किया गया।

बस्तर में पहली बार राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन

जगदलपुर। बस्तर में पहली बार राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा 8 और 9 अक्टूबर को जगदलपुर में आयोजित सम्मेलन में देशभर के वरिष्ठ अधिकारी ‘सहकार से समृद्धि’ की कार्ययोजना पर मंथन करेंगे। सम्मेलन भारत सरकार के सहकारिता विभाग के सचिव आशीष कुमार भूटानी की अध्यक्षता में होगा। इसमें अतिरिक्त सचिव एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के प्रबंध संचालक पंकज बंसल तथा भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव सिद्धार्थ जैन भी शामिल होंगे। सम्मेलन में मल्टीपर्सपेक् प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (एम-पैक्स) और दुग्ध समितियों के गठन, एम-पैक्स कंयूटरीकरण, सहकारिता में डिजिटल तकनीक के उपयोग, भंडारण क्षमता के विस्तार और सहकारी बैंकिंग के सशक्तिकरण पर विशेष चर्चा होगी। एम-पैक्स से उर्वरक वितरण और बहुराज्यीय सहकारी संस्थाओं से समन्वय पर भी विचार कर अगले तीन महीनों की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

वारदात के 3 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार

चरचा/कोरिया। थाना चरचा क्षेत्र के स्टाफ कॉलोनी स्थित कालरी ड्राटर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात के महज तीन घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की रकम से खरीदा गया मोबाइल फोन और नगदी बरामद की है। पुलिस के अनुसार, 6 अक्टूबर 2026 को अमन सिंह निवासी स्टाफ कॉलोनी चरचा ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि उसकी मां 5 अक्टूबर को सुबह करीब 10 बजे चरचा आंशो कार्यालय काम करने गई थीं। दोपहर करीब 2 बजे घर लौटने पर पता चला कि बाथरूम के पास स्थित रोशनदान को तोड़कर अज्ञात चोर घर में दाखिल हुआ और अलमारी में रखी 50 एवं 100 रुपये के नोटों में कुल 15 हजार रुपये नगद तथा फल एवं अन्य खाने-पीने का सामान चोर कर ले गया। शिकायत पर थाना चरचा में अपराध क्रमांक 151/2026, धारा 305(ए) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस को संदेही शमशेर बसोर उर्फ गगन



बसोर, पिता दिलीप बसोर, निवासी घुटरी दफाई चरचा के संबंध में जानकारी मिली। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी ने चोरी की रकम से एक मोबाइल फोन खरीदा है और शेष रकम खर्च कर रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर उनके निर्देश एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक के.एस. गौतम के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर संदेही को तलब कर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने प्रार्थी के घर चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी के बताए अनुसार पुलिस ने चोरी की रकम से खरीदा गया मोबाइल फोन, कीमत करीब 7,500 रुपये, तथा 970 रुपये नगद बरामद कर जब्त किए। पुलिस ने आरोपी शमशेर उर्फ गगन बसोर, उम्र 22 वर्ष, निवासी घुटरी दफाई चरचा को 6 अक्टूबर को शाम 4:10 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

संक्षिप्त समाचार

गृह मंत्री का निज सचिव बताकर सरकारी नौकरी लगाने का झांसा

रायपुर। गृह मंत्री का निज सचिव बताकर सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिविल लाईन थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धारा 318 (2), 319 (2), 336 (3), 340, 3 (5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की है।
प्राप्ती बोस्टो तांडी ने सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी संतराम यादव एवं आदित्य मोहन पंडा ने का प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क होने की बात कहते हुए शासकीय नौकरी लगाने का झांसा दिया। आदित्य ने स्वयं को गृहमंत्री का निज सहायक होने का झूठा पहचान बताकर 70000 रुपए लेकर नौकरी नहीं लगाई। उसके साथ-साथ अन्य लोगों से भी धोखाधड़ी की गई है। प्राप्ती के रिपोर्ट पर सिविल लाइन थाना में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।घटना के संबंध में प्राप्ती सहित गवाहों से विस्तृत पूछताछ के बाद आरोपी कल्प विहार, रायपुर निवासी आदित्य मोहन पण्डा पिता अनिल पण्डा (23 साल) और हिमाचला हाईस्ट, देवपुरी, रायपुर निवासी संतराम यादव पिता बलराम यादव (38 साल) को हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर आरोपियों ने इसी प्रकार से नौकरी लगाने, ट्रांसफर कराने के नाम पर करीब 15 लोगों से करीब 25 लाख लेने की बात स्वीकार की। आरोप की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आरोपियों से पूछताछ जारी रखे हुए है।

राज्य ओपन स्कूल की मुख्य/अवसर परीक्षा नवम्बर 2026 की समय-सारिणी जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी मुख्य/अवसर परीक्षा नवम्बर 2026 की समय-सारिणी निर्धारित कर दी गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हाईस्कूल की परीक्षा 23 नवम्बर से प्रारंभ होकर 8 दिसम्बर तक तथा हायर सेकण्डरी की परीक्षा 23 नवम्बर से प्रारंभ होकर 10 दिसम्बर तक आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के अधिकारियों ने बताया कि परीक्षार्थी अपनी परीक्षा से संबंधित विषयवार समय-सारिणी को जानकारी अपने समीपस्थ अध्ययन केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा के लिखित समय-सारिणी छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की कार्यालयीन वेबसाइट www.sos.cg.nic.in पर भी उपलब्ध है, जहां से छात्र-छात्राएं समय-सारिणी डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा समस्त परीक्षार्थियों से अपील की गई है कि वे परीक्षा की तिथियों एवं समय की जानकारी समय रहते प्राप्त कर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित हों।

संत ज्ञानेश्वर स्कूल में शत- प्रतिशत उपस्थिति वाले बच्चे पुरस्कृत

रायपुर। संत ज्ञानेश्वर स्कूल में शत- प्रतिशत उपस्थिति वाले बच्चों को प्राचार्य मनीष गोवर्धन और वरिष्ठ शिक्षक अखिल खरे ने पुरस्कृत किया। महाराष्ट्र मंडल की शाला में शत- प्रतिशत उपस्थिति वाले बच्चों को प्रतिमाह पुरस्कृत किया जा रहा है, ताकि अन्य बच्चे भी प्रेरित हो और क्लास में शत-प्रतिशत उपस्थिति के लिए प्रतिबद्ध हों। शिक्षिका अपर्णा आठले ने बताया कि सितंबर में शत-प्रतिशत उपस्थिति वाले बच्चों में पहली से ईशांत वर्मा, साई राज सिंह, संजना कैवर्त और रेयांश वर्मा शामिल रहे। वहीं दूसरी से अदिति गायकवाड़, अभिज्ञा शुक्ला, रुद्र साहू और श्रेया वर्मा को पुरस्कृत किया गया। तीसरी से अनुष्का बारले, दिव्या साहू, दिव्यांशी साहू, कार्तिक दास, नैना साव, प्रज्ञा दीप दास, शिखा साहू, यश गुसा, गीतांजलि राव और रुद्राक्षी राजवाड़े को शत- प्रतिशत उपस्थिति के लिए इनाम दिया गया। अपर्णा आठले के अनुसार कक्षा चौथी से रोहन साहू, सुहाणी आठले, अजय सिंह राजपूत और दीपिका साहू भी सौ प्रतिशत उपस्थिति वाले बच्चों में शामिल रहे। पांचवीं में सौरव राउत, लव पाठक, मोक्ष साहू, डी पल्लवी, तन्मय साहू, प्रियांशी राजवाड़े और तेजस्वी वर्मा की उपस्थिति पुरस्कृत करने योग्य रही। इस दौरान बच्चों को जंक फूड और हेल्दी फूड के बारे में भी बताया गया। जिसमें पर के खाने को प्राथमिकता दी जाए, जो कि हमारे सेहत के लिए अत्यावश्यक है।

मथुरा व भूतेश्वर स्टेशन में याई रिमांडिलिंग कार्य के चलते ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेगी

रायपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के साथ ही ट्रेनों के परिचालन गतिशीलता संबंधी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल के मथुरा स्टेशन (फेस- 11) एवं भूतेश्वर स्टेशन में यार्ड रिमांडिलिंग हेतु प्री-एनआई व एनआई का कार्य किया जायेगा। इसके/गलस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने/फुजरने वाली कुछ गाडियों प्रभावित रहेगी। 10 अक्टूबर को निजामुद्दीन से चलने वाली गाडी संख्या 22868 निजामुद्दीन-दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग व्हाया निजामुद्दीन-गाजियाबाद-मितावली-आगरा कैंट मार्ग होकर दुर्ग आएगी। 10 अक्टूबर को फिरोजपुर से चलने वाली गाडी संख्या 20424 फिरोजपुर-सिवनी पातालकोट एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग व्हाया दिल्ली सफदरगंज-गाजियाबाद-मितावली-आगरा कैंट मार्ग होकर सिवनी जायेगी। 10 अक्टूबर को योगनगरी ऋषिकेश से चलने वाली गाडी संख्या 18478 योगनगरी ऋषिकेश-पुरी कलिंग उत्कल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग व्हाय मेरठ सिटी-खुर्जा-मितावली-आगरा कैंट मार्ग होकर पुरी जायेगी। 9 अक्टूबर को विशाखापटनम से चलने वाली गाडी संख्या 20807 विशाखापटनम-अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग व्हाया आगरा कैंट- मितावली-गाजियाबाद-नई दिल्ली मार्ग होकर अमृतसर जायेगी। यात्रीगण कृपया यात्रा से पूर्व ट्रेन की विस्तृत जानकारी रेलवन ऐप से अवश्य प्राप्त कर लें।

राजधानी/छत्तीसगढ़

सिंगापुर दौरे से लौटे मुख्यमंत्री साय, बोले-

43,600 करोड़ के विदेशी निवेश प्रस्ताव मिले, सभी एमओयू धरातल पर उतरेंगे

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सिंगापुर के तीन दिवसीय दौरे के बाद छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। मुख्यमंत्री 3 से 6 अक्टूबर तक सिंगापुर प्रवास पर थे। रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान अपने दौरे की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि सिंगापुर में आयोजित इंडिया ग्रीथ फोरम 2026 कार्यक्रम में शामिल होकर छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के सामने रखा गया। इस दौरान प्रदेश में निवेश के लिए 43 हजार 600 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मिले हैं।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि सिंगापुर के उद्योग जगत से जुड़े कई प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई और उन्हें छत्तीसगढ़ आने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि इन निवेश प्रस्तावों से प्रदेश में रोजगार और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

मीडिया से चर्चा में सीएम साय ने कहा कि सिंगापुर दौरे के दौरान एनर्जी कैपिटल ग्लोबल की ओर से 41 हजार 750 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव मिला है। वहीं एग््री बिजनेस वैल्यू इंटरनेशनल कंपनी ने करीब 350 करोड़



रुपये निवेश का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा सन स्ट्रीम ग्रीन एनर्जी की ओर से सोलर सेक्टर में करीब 1,500 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव मिला है। कंपनी बैटरी स्टोरेज और उससे जुड़े कंपोनेंट के क्षेत्र में काम करेगी।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि आईटी एजुकेशन सर्विस के साथ भी एमओयू हुआ है। उन्होंने संस्था के आईटी परिसर का भ्रमण किया, जो विश्व प्रसिद्ध कौशल विकास मॉडल है।

निवेश प्रस्तावों के प्रदेश में धरातल पर उतरने को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार जो भी एमओयू कर रही है, उसे पूरी जांच-परख के बाद कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को आश्वासन करना चाहते हैं कि इन समझौतों और प्रस्तावों को धरातल पर

रायपुर में आवारा सांड का आतंक 15 लोगों पर किया हमला

रायपुर। राजधानी रायपुर के डीडी नगर इलाके में एक आवारा सांड के आतंक से लोगों में दहशत फैल गई है। सांड ने अलग-अलग जगहों पर करीब 15 लोगों पर हमला किया है। हमले में पूर्व महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कल्पना पटेल समेत कई लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सांड के हमले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बच्चे को गोद में लिए एक बुजुर्ग पर अचानक हमला करता नजर आ रहा है। सांड के हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और उनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पूर्व महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कल्पना पटेल को भी चोटें आई हैं। उन्हें उपचार के लिए बालाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार हमलों की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सांड को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। टीम ने ट्रैकिलाइजर डार्ट का इस्तेमाल कर सांड को बेहोश किया, जिसके बाद उसे सुरक्षित तरीके से काबू में लिया गया। घटना के बाद गौ सेवकों ने सांड के रेबीज से संक्रमित होने की आशंका जताई है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। घटना को लेकर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भी चिंता जताई है। उन्होंने राजधानी में आवारा पशुओं की समस्या को लेकर नगर प्रशासन पर सवाल उठाए।

वेतन विसंगति और ग्रेज्यूटी को लेकर फूटा गुस्सा

■ जय अम्बे इमरजेंसी सर्विस के मुख्य दफ्तर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कर्मचारी

रायपुर। ग्रेज्यूटी, वेतन विसंगति और लंबित भुगतान की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश 108-102 कर्मचारों संघ ने बुधवार को राजधानी रायपुर में जय अंबे इमरजेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यालय का घेराव किया। कर्मचारियों ने अवती विहार स्थित ग्लोबल टावर में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है। संघ का कहना है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

संघ के अनुसार, जय अंबे इमरजेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने सितंबर 2019 से मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ में 108

संजीवनी एक्सप्रेस सेवा का संचालन किया था। टेंडर खत्म होने के बाद कर्मचारियों की ग्रेज्यूटी और बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। कर्मचारियों का दावा है कि छह महीने बीतने के बाद भी उन्हें उनका भुगतान नहीं मिला है। कर्मचारियों ने बताया कि इससे पहले 24 अगस्त को कंपनी के प्रधान कार्यालय में एक दिवसीय घेराव और धरना प्रदर्शन किया गया था। उस दौरान कंपनी की ओर से लिखित आश्वासन दिया गया था कि 10 कार्य दिवस में उपस्थित कर्मचारियों और 30 कार्य दिवस में सभी कर्मचारियों की ग्रेज्यूटी के साथ वेतन विसंगति का भुगतान कर दिया जाएगा। संघ का आरोप है कि तय समय बीतने के बावजूद आश्वासन के अनुसार भुगतान नहीं किया गया।

ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय हेलीकॉप्टर के बीमा दावे के निराकरण में चार साल से अधिक समय तक हुई देरी के मामले में कड़ा कदम उठाते हुए द ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ह्यूब्लर) को तीन वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। विमानन संचालनालय ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कंपनी के विरुद्ध यह कार्रवाई की है।

मामला मई 2022 में रायपुर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुए राज्य शासन के हेलीकॉप्टर से संबंधित रहा। शासन ने इसे सार्वजनिक धन और शासन द्वारा हेलीकॉप्टर का बीमा ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी से कराया गया था और निर्धारित बीमा प्रीमियम का पूर्ण भुगतान किया गया था। दुर्घटना के बाद राज्य शासन की ओर से बीमा दावा प्रस्तुत किया गया, लेकिन कंपनी द्वारा इस दावे को चार वर्ष से अधिक समय तक लंबित रखा गया और अंततः अगस्त 2026 में इसे अस्वीकार कर दिया गया।

विमानन संचालनालय ने पूरे



प्रकरण के परीक्षण में पाया कि सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े बीमा दावे के निराकरण में अत्यधिक विलंब हुआ और राज्य शासन के प्रकरण के निपटारे में कंपनी का रवैया असंगत रहा। शासन ने इसे सार्वजनिक धन और शासकीय हित से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए कार्रवाई की है।

अधिकारियों के अनुसार शासकीय हेलीकॉप्टर सार्वजनिक संपत्ति है, जिसकी खरीदी और बीमा में जनता का पैसा लगा है। ऐसी स्थिति में बीमा दावे को वर्षों तक लंबित रखने का आर्थिक प्रभाव अंततः सार्वजनिक संसाधनों पर पड़ता है। शासन का स्पष्ट मत है कि सरकार के साथ कार्य करने वाली प्रत्येक सेवा

प्रदाता संस्था को अपनी संविदात्मक जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं का समयबद्ध रूप से पालन करना होगा।

राज्य शासन ने इस मामले में प्राकृतिक न्याय और निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया। ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कंपनी ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया और उसे व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया। कंपनी का पक्ष सुनने और उपलब्ध तथ्यों एवं विमलेखों का परीक्षण करने के बाद विमानन संचालनालय ने कारणों सहित आदेश पारित करते हुए कंपनी को तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया।

अधिकारियों ने कहा कि शासन के साथ काम करने वाले प्रत्येक सेवा प्रदाता के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आवश्यक है। सार्वजनिक दावों के निपटारे में अनावश्यक विलंब को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के साथ कार्य करने वाली प्रत्येक सेवा

कार्डियक अरेस्ट के बाद 15 प्रतिशत ईएफवाले 73 वर्षीय मरीज का सफल इलाज

रायपुर। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के हार्ट, चेस्ट एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग ने एक बार फिर से अत्यंत जटिल एवं चुनौतीपूर्ण कार्डियक सर्जरी में सफलता हासिल की है। विभागाध्यक्ष डॉ. कृष्णकांत साहू और उनकी टीम ने 73 वर्षीय मरीज, जिसे कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में अस्पताल लाया गया था, का सफलतापूर्वक कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग एवं एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट कर उसे नया दिया।

मरीज को गंभीर अवस्था में अम्बेडकर अस्पताल के आपातकालीन विभाग में लाया गया था। उस समय उसकी हृदय गति रुक चुकी थी। आपातकालीन विभाग की टीम ने तत्काल कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एवं डीसी शॉक और डिफिब्रिलेशन - चिकित्सा जगत में हृदय की असामान्य और जानलेवा धड़कनों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं) देकर मरीज को पुनर्जीवित किया। हृदय की धड़कन वापस आने के बाद मरीज को वेंटिलेटर पर रखा गया और विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उपचार शुरू किया गया।

कार्डियक अरेस्ट से सफलतापूर्वक रिवाइव होने के बाद भी मरीज की स्थिति बेहद गंभीर थी। जांच में उसकी हृदय की पंपिंग क्षमता केवल लगभग 15 प्रतिशत पाई गई। इसके साथ ही मरीज की तीनों प्रमुख कोरोनरी धमनियों में ब्लॉकेज था तथा एओर्टिक वाल्व में गंभीर सिक्कुडन पाई गई। मरीज को कुछ दिनों तक वेंटिलेटर सपोर्ट एवं गहन चिकित्सा निगरानी में रखा गया। स्थिति में सुधार होने पर वेंटिलेटर हटाया गया और इसके बाद उसे कार्डियक सर्जरी विभाग में स्थानांतरित किया गया।



ऑपरेशन से पहले मरीज को लगभग 23 दिनों तक कार्डियक सर्जरी आईसीयू में रखकर उसकी स्थिति को स्थिर करने का प्रयास किया गया। इस दौरान मरीज को एक्यूट किडनी इंजरी (किडनी फेल्योर) की समस्या भी हुई और कुछ समय के लिए पेशाब का आना बंद हो गया था। स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए प्रारंभिक अवस्था में मरीज ऑपरेशन के लिए उपयुक्त नहीं था। धीरे-धीरे स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद विशेषज्ञों की टीम ने उसे ऑपरेशन के लिए तैयार किया।

मरीज की उम्र, हाल ही में हुए कार्डियक अरेस्ट के बाद बेहद कम हृदय की पंपिंग क्षमता, तीनों कोरोनरी धमनियों में ब्लॉकेज तथा गंभीर एओर्टिक स्ट्रेनोसिस को देखते हुए ऑपरेशन अत्यंत जोखिमपूर्ण था। मरीज के परिजनों को उसकी गंभीर स्थिति तथा ऑपरेशन से जुड़े संभावित जोखिमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। यहाँ तक की मरीज का ऑपरेशन थिएटर से निकल पाना मुश्किल है,इसके बावजूद परिजनों ने ऑपरेशन के लिए सहमत दी। सीटीवीएस विभागाध्यक्ष एवं मुख्य सर्जन डॉ. कृष्णकांत साहू ने बताया कि मरीज की स्थिति को देखते हुए उसका कोरोनरी धमनी बाईपास ग्राफ्टिंग किया गया। हृदय की बंद कोरोनरी धमनियों में वेन एवं आर्टरी कंइयूट का उपयोग करते हुए बाईपास बनाया गया।

साय समेत नेता-कार्यकर्ताओं ने 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का लिया संकल्प

भाजपा का सेवा संकल्प अभियान : प्रदेश में 38 जगह बनेंगे सेवा ज्योति संकल्प चौक



कराई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सेवा संकल्प अभियान और विकसित भारत संकल्प सभा को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि वह स्वस्थ रहें और लंबे समय तक देश की सेवा करते रहें।

साय ने कहा कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चल रहा है। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी को 140 करोड़ भारतवासियों का सहयोग मिला है और वह रात-दिन देश के सुख-दुख के

लिए काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री 'सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को भी प्रधानमंत्री का काफी आशीर्वाद मिला है और जब प्रदेश के विकास की बात लेकर उनके पास जाते हैं तो

उम्मीद से ज्यादा समर्थन मिलता है। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित राज्य बनाने का संकल्प है। उन्होंने अपने हालिया सिंगापुर दौरे का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री के मुताबिक, दौरे के दौरान उन्होंने चार दिनों तक उद्योग जगत और बिजनेस फेडरेशन से जुड़े लोगों से मुलाकात की।

साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उद्योग जगत में भरोसा है और उनकी ओर से जो भी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ को मिलेगी, उसे पूरा किया जाएगा। इस दौरान सीएम साय समेत नेता-कार्यकर्ताओं ने

नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन ने किया विरोध प्रदर्शन

■ ग्रेड पे एवं वेतनमान की मांग को लेकर जगदलपुर, कांकेर और राजनांदागांव मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग संवर्ग ने जताया विरोध

रायपुर। ग्रेड पे एवं वेतनमान सहित विभिन्न मांगों को लेकर नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के बैनर तले प्रदेश के तीन प्रमुख शासकीय मेडिकल कॉलेजों के नर्सिंग संवर्ग द्वारा चिकित्सालय परिसर में दो घंटे का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के माध्यम से नर्सिंग संवर्ग ने अपनी लंबित मांगों की ओर शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांगों के शीघ्र निराकरण की अपील की।

नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़



के पदाधिकारियों ने बताया कि ग्रेड पे एवं वेतनमान की मांग को लेकर संघ द्वारा लगातार चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में अपनी मांगों को शासन एवं प्रशासन के स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से 6 अक्टूबर 2026 को भी जगदलपुर, कांकेर

एवं राजनांदागांव मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग संवर्ग द्वारा सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया था। संघ ने बताया कि आंदोलन के अगले चरण में 8 अक्टूबर 2026 को दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक स्कूटी रैली निकाली जाएगी। रैली के माध्यम से नर्सिंग संवर्ग अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम जापन संबंधित कलेक्टर को सौंपेगा।

संघ पदाधिकारियों ने कहा कि यदि निर्धारित समय-सीमा में मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होती है, तो 18 नवंबर 2026 से संघ द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। संघ ने शासन से नर्सिंग संवर्ग की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शीघ्र उचित निर्णय लेने की मांग की है।

<

कांग्रेस हाईकमान का अजीब नोटिस

डॉ. श्रीगोपाल नारसन

बीमारी से उभरने के लंबे समय बाद उत्तराखंड की जनता के बीच आमजन का धन्यवाद करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा निकाली जा रही धन्यवाद यात्रा से भाजपा को मिर्ची लगती तो समझ में आता,लेकिन यहाँ तो स्वयं कांग्रेस ही उन्हें ऐसा करने से रोक रही है।जबकि अभी तक कि हरीश रावत की धन्यवाद यात्राओं में उमड़ा जन सैलाब टंडी पड़ी कांग्रेस को ऑक्सीजन मिलने का प्रमाण कहा जा सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश प्रभारी कुमार शैलजा के बीच इस यात्रा को लेकर नया विवाद छिड़ गया है।जो राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों को दरकिनार करते हुए हरीश रावत ने अपनी धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप शुरू कर दी है, जिससे पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह सतह पर आ गई है।विदित हो उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से चर्चा के बाद हरीश रावत को पत्र लिखकर इस यात्रा को रोकने और स्पष्टीकरण देने को कहा था। शैलजा का तर्क है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी से बिना चर्चा किए समानांतर यात्रा निकालना पार्टी के हित में नहीं है। इसके बावजूद, हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर चुनौती बड़ी है, अब रुकना नहीं लिखकर अपनी यात्रा जसपुर से शुरू कर दी है।इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब हरीश रावत की इस यात्रा में कांग्रेस की चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल भी उनके साथ नजर आए। प्रीतम सिंह और हरीश रावत की यह जुगलबंदी कांग्रेस के अन्य गुटों के लिए हैरान करने वाली है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि उत्तराखंड के बड़े नेता संगठन से जुड़े हाईकमान के मनमाने फैसलों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हरीश रावत पिछले कुछ समय से पार्टी कार्यक्रमों में खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे थे। आगामी विधासभा चुनावों से पहले इसे तरह की समानांतर गतिविधियां राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच गुटबाजी का संकेत है,वही एकजुटता का गलत संदेश दे सकती हैं।कांग्रेस के इस अंदरूनी घमासान पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है कि कांग्रेस पहले से ही गुटों में बंटी हुई थी, लेकिन प्रभारी कुमारी शैलजा के पत्र ने अब इस बात पर मुहर लगा दी है।यह स्थिति कांग्रेस के लिए काफी नाजुक बन गई है। यदि कुमारी शैलजा और आलाकमान हरीश रावत के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कदम उठाते हैं, तो चुनावों से ठीक पहले हरीश रावत जैसे कदावर और जनाधार वाले नेता की नाराजगी कांग्रेस के चुनावी समीकरणों को पूरी तरह बिगाड़ सकती है।वही कांग्रेस हाईकमान को सोचना यह भी चाहिए कि हरीश रावत धन्यवाद यात्रा निकाल कर गलत क्या कर रहे हैं?उनकी सक्रिय ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में न सिर्फ जोश भरा है बल्कि कांग्रेस के पक्ष में बदलाव का वातावरण भी विकसित किया है।हाईकमान द्वारा नियुक्त प्रभारी केवल अपना स्वागत सम्मान करने के कोई ऐसा ठोस कार्य नहीं करते ,जिससे वे ग्रास र्ट तक अपनी पहुँच बना सके।उत्तराखंड में काफी समय से भाजपा की सरकार है,कभी गलत टिकट बंटवारा तो कभी कथित रूप से पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप के चलते कांग्रेस हर बार जीती बाजी सिर्फ इसलिए हार जाती है क्योंकि उसके द्वारा जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर दलबदलूओं या फिर अवसरवादियों को आगे बढ़ाया गया।

भारतीय दार्शनिक सम्रदाय

15- ब्राह्मणिक के स्थान में वैदिकं शब्द का प्रयोग

गतांक से आगे...

जहां तक ब्राह्मण वर्ग का सवाल है, यह ठीक है कि अधिकतर ब्राह्मण पुरानी परम्परा को मानने वाले वैदिक ही थे, परन्तु यह भी स्पष्ट है कि बौद्धों के अनेक प्रमुख आचार्य जैसे दिडनाग, धर्मकीर्ति आदि ब्राह्मण ही थे। वस्तुत: बात यह है कि जो ब्राह्मण क्रान्तिकारी प्रवृत्ति के होते थे वे बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाते थे। इसीलिए प्राचीन परम्परागत प्रवृत्ति के लिए ब्राह्मणिक शब्द का प्रयोग न करके वैदिक शब्द का प्रयोग इस पुस्तक में किया गया है।

16 दर्शन, मीमांसा और फिलासफी

पाश्चात्य देशों में साहित्य या वाडमय के जिस विभाग के लिए फिलासफी शब्द का प्रयोग होता है उसके लिए हमारे यहां बहुत दिनों से दर्शन शब्द का प्रयोग होता रहा है, जैसे बौद्ध दर्शन या वेदान्त दर्शन आदि। आधुनिक समय में भारतीय भाषाओं में फिलासफी के लिए दर्शन शब्द का प्रयोग सर्व सम्मत

सा हो गया है और यह प्रयोग प्राचीन परम्परा के अनुसार होने से ठीक भी है, परन्तु ध्यान देने से यह प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में संस्कृत वाडमय में दर्शन शब्द न होकर फिलासफी के लिए मीमांसा शब्द का प्रयोग हुआ था। इसी लिए वेद के दो विभाग कर्मकाण्ड सम्बन्धी ब्राह्मणग्रन्थ और ज्ञानकाण्ड सम्बन्धी उपनिषदों पर आश्रित दर्शनों को पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा इन शब्दों से व्यवहृत किया गया था यह भी बड़ी रोचक बात है कि फिलासफी और मीमांसा शब्दों के यौगिक अर्थ भी समान ही है। फिलासफी शब्द का अर्थ है ज्ञान का प्रेम। इसी प्रकार मीमांसा का शब्दार्थ है मनन या ज्ञान की इच्छा (मन्- जानना, समझना इच्छार्थक प्रत्यय + अ प्रत्यय), इस लिए मीमांसा का अर्थ होता है किसी विषय की परीक्षा इस प्रकार फिलासफी के अर्थ में मीमांसा शब्द बहुत ही उपयुक्त है।



पीएम नरेंद्र मोदी : सेवा, संकल्प और राष्ट्रनिर्माण के 25 वर्ष

देवेंद्र फडणवीस

राजनीति में अनेक नेता आते हैं। कुछ नेता चुनाव जीतते हैं, कुछ सरकारें चलाते हैं; लेकिन कुछ नेतृत्व ऐसे होते हैं, जो देश के विकास के बारे में सोचने के तरीके को ही बदल देते हैं। नरेंद्र मोदीजी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों का सफर ऐसे ही परिवर्तन की यात्रा है। 7 अक्तूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदीजी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष 7 अक्तूबर 2026 को पूर्ण हो रहे हैं।

यह 25 वर्षों का सफर केवल एक राजनीतिक नेता के लंबे कार्यकाल का आकलन नहीं है; बल्कि यह भारत के विकास की बदलती दिशा, जनभागीदारी के माध्यम से राष्ट्रनिर्माण और सामान्य नागरिक की आकांक्षाओं को केंद्र में रखने वाले नेतृत्व की यात्रा है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रशासन का अनुभव प्राप्त करने के बाद 26 मई 2014 को उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली।

मई 2026 में उनके प्रधानमंत्री पद के 12 वर्ष पूरे हुए। आज भी उनके नेतृत्व में तेज गति से विकास हो रहा है। गुजरात से दिल्ली तक का यह सफर आज भारत के विकास की व्यापक संकल्पना से जुड़ गया है। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महाराष्ट्र है। उद्योग, व्यापार, कृषि, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन की समृद्ध परंपरा वाले महाराष्ट्र को राष्ट्रीय विकास के केंद्र में लाने में केंद्र सरकार के विभिन्न निर्णयों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2014 से 2026 तक का कालखंड महाराष्ट्र के बुनियादी ढांचे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण साबित हुआ है।

गुजरात के वडनगर जैसे छोटे शहर और एक सामान्य परिवार से आगे बढ़े नरेंद्र मोदीजी के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत सामाजिक संगठन के कार्य से हुई। 1974 के गुजरात छात्र आंदोलन में भागीदारी, आपातकाल के दौरान भूमिगत जनजागरण और भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्य का



लंबा अनुभव उनके सफर के महत्वपूर्ण पड़ाव रहे हैं।

7 अक्तूबर 2001 को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पहली बड़ी परीक्षाओं में से एक था 2001 के भूकंप के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण का कार्य। इस दौरान प्रशासन के कामकाज में लक्ष्य, आंकड़े, समयसीमा और वास्तविक परिणामों को महत्व देने वाली कार्यशैली विकसित हुई। कितने घर बनाए गए, कितने परिवारों का पुनर्वास हुआ,

कौन-सा काम पूरा हुआ और कहाँ अड़चनें हैं – इसका आकलन करने की पद्धति आगे चलकर उनकी प्रशासनिक शैली की पहचान बनी। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदीजी के कार्यकाल में ऊर्जा, पानी, कृषि, उद्योग, शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्रों में विभिन्न पहल की गई। वाइब्रेंट गुजरात समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशकों को गुजरात की ओर आकर्षित किया गया।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2001 में एक लाख करोड़ रुपए से कम रहने वाला गुजरात का निर्यात मोदीजी के मार्गदर्शन में चार लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा। 2014 में प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद नरेंद्र मोदीजी ने भारत के

ज्ञान/मीमांसा

कांग्रेस-सपा को गठबंधन के भीतर विश्वास की जरूरत

सौरभ वार्णेय

समझ नहीं आता कि राजनीतिक पार्टी हर बार चुनाव से पहले कसमस में क्यों उलझ कर रह जाती है। जहां एक ओर आगामी युवा देश की कमान ऐसे नेता को सौंपना चाहता है जो उनका नेतृत्व कर सकें। वहीं चुनाव पूर्व रणनीति का े समझने की जगह जनता के सेंटीमेंट को समझ ही नहीं पा रही ? फिर चुनाव बाद पश्याताप करते दिखाई हैं जैसे ममता दीदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी सरगमी बढ़ने के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह की खींचतान सामने आ रही है, उसने विपक्षी एकता के दावों की वास्तविकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर दोनों दल भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले मजबूत राजनीतिक चुनौती पेश करने की तैयारी में जुटे हैं, दूसरी ओर गठबंधन के भीतर सीटों की संख्या, राजनीतिक प्रभाव और नेतृत्व की प्राथमिकताओं को लेकर असहजता लगातार सामने आ रही है। सवाल केवल यह नहीं है कि सपा कितनी सीटें चाहती है और कांग्रेस कितनी सीटों पर दावा कर रही है। असली सवाल यह है कि क्या दोनों दल उस राजनीतिक समझ और परिपक्वता का परिचय दे पाएंगे, जिसकी अपेक्षा एक प्रभावी गठबंधन से की जाती है?

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह कहना कि बात सीट की नहीं, जीत की है इसके मायने अलग हैं वह समझ रहे है कि बिना गठबंधन के कुछ नहीं हो सकता? इस पूरे विवाद के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश है। उन्होंने गठबंधन की जीत को सीटों की संख्या से ऊपर रखते हुए कहा कि मकसद स्पष्ट हो तो साथ मिलकर मंजिल हासिल की जा सकती है। उनका यह संदेश सपा-कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान के बीच एक तरह से राजनीतिक संयम की अपील भी है। लेकिन राजनीति में केवल संदेश काफी नहीं होते। संदेश को जमीन पर उतारने की इच्छाशक्ति और संगठनात्मक क्षमता भी चाहिए। यही वह बिंदु है जहां सपा-कांग्रेस गठबंधन की असली परीक्षा शुरू होती है।

चुनावी गठबंधन कोई ऐसा समझौता नहीं होता जिसमें केवल सीटों का गणित बैठा दिया जाए। गठबंधन का अर्थ है कि एक-दूसरे के राजनीतिक अस्तित्व का सम्मान, साझा रणनीति, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय और मतदाताओं को एक स्पष्ट संदेश। यदि शीर्ष नेतृत्व मंच पर एकता की बात करे, लेकिन स्थानीय स्तर पर दोनों दलों के नेता चुनाव से पहले कसमस में क्यों उलझ कर रह जाती है। जहां एक ओर आगामी युवा देश की कमान ऐसे नेता को सौंपना चाहता है जो उनका नेतृत्व कर सकें। वहीं चुनाव पूर्व रणनीति का े समझने की जगह जनता के सेंटीमेंट को समझ ही नहीं पा रही ? फिर चुनाव बाद पश्याताप करते दिखाई हैं जैसे ममता दीदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी सरगमी बढ़ने के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह की खींचतान सामने आ रही है, उसने विपक्षी एकता के दावों की वास्तविकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर दोनों दल भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले मजबूत राजनीतिक चुनौती पेश करने की तैयारी में जुटे हैं, दूसरी ओर गठबंधन के भीतर सीटों की संख्या, राजनीतिक प्रभाव और नेतृत्व की प्राथमिकताओं को लेकर असहजता लगातार सामने आ रही है। सवाल केवल यह नहीं है कि सपा कितनी सीटें चाहती है और कांग्रेस कितनी सीटों पर दावा कर रही है। असली सवाल यह है कि क्या दोनों दल उस राजनीतिक समझ और परिपक्वता का परिचय दे पाएंगे, जिसकी अपेक्षा एक प्रभावी गठबंधन से की जाती है?

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह कहना कि बात सीट की नहीं, जीत की है इसके मायने अलग हैं वह समझ रहे है कि बिना गठबंधन के कुछ नहीं हो सकता? इस पूरे विवाद के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश है। उन्होंने गठबंधन की जीत को सीटों की संख्या से ऊपर रखते हुए कहा कि मकसद स्पष्ट हो तो साथ मिलकर मंजिल हासिल की जा सकती है। उनका यह संदेश सपा-कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान के बीच एक तरह से राजनीतिक संयम की अपील भी है। लेकिन राजनीति में केवल संदेश काफी नहीं होते। संदेश को जमीन पर उतारने की इच्छाशक्ति और संगठनात्मक क्षमता भी चाहिए। यही वह बिंदु है जहां सपा-कांग्रेस गठबंधन की असली परीक्षा शुरू होती है।

चुनावी गठबंधन कोई ऐसा समझौता नहीं होता जिसमें केवल सीटों का गणित बैठा दिया जाए। गठबंधन का अर्थ है कि एक-दूसरे के राजनीतिक अस्तित्व का सम्मान, साझा रणनीति, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय और मतदाताओं को एक स्पष्ट संदेश। यदि शीर्ष नेतृत्व मंच पर एकता की बात करे, लेकिन स्थानीय स्तर पर दोनों दलों के नेता

क्रमशः ...



एक-दूसरे के खिलाफ बयान दें, तो जनता के बीच गठबंधन की विश्वासनीयता स्वाभाविक रूप से कमजोर होगी। उत्तर प्रदेश में यह खतरा और भी बढ़ा है, क्योंकि यहां चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों के बीच भी लड़ा जाता है। प्रत्येक सीट का अपना अलग सामाजिक समीकरण, स्थानीय नेतृत्व और राजनीतिक इतिहास होता है। ऐसे में केवल सीटों की संख्या के आधार पर फार्मूला तैयार करना पर्याप्त नहीं होगा। यह देखना होगा कि किस क्षेत्र में किस दल का संगठन मजबूत है, किस उम्मीदवार की स्वीकार्यता अधिक है और कौन-सा प्रत्याशी विपक्षी मतों को एकजुट कर सकता है।

यही वह व्यावहारिक राजनीति है जिसे समझे बिना गठबंधन का गणित कागज पर तो सुंदर दिखाई दे सकता है, लेकिन चुनावी मैदान में बिखर सकता है। भाजपा ने सपा-कांग्रेस के बीच जारी मतभेदों को अपने राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का गठबंधन को लठबंधन कहना इसी रणनीति का हिस्सा है। भाजपा के लिए विपक्षी गठबंधन के भीतर का प्रत्येक मतभेद राजनीतिक अवसर है। विपक्ष जितना अधिक एक-दूसरे के खिलाफ बोलेगा, भाजपा उतना ही यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि उसके सामने खड़ा गठबंधन सत्ता का विकल्प बनने से पहले ही आपसी संघर्ष में उलझ गया है। भाजपा के खिलाफ लड़ाई केवल चुनावी भाषणों से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए विपक्षी दलों को अपने भीतर की कमजोरियों पर भी विजय हासिल करनी होगी। यह विडंबना है कि जो दल लोकतंत्र, संविधान, सामाजिक न्याय और जनहित के बड़े मुद्दों को लेकर एक मंच पर आने की बात करते हैं, वे स्वयं सीटों के प्रश्न पर सार्वजनिक असहमति का प्रदर्शन करने लगें। जनता स्वाभाविक रूप से पूछेगी कि जब सत्ता की साझेदारी अभी हुई भी नहीं है तो सीटों की साझेदारी पर इतना संघर्ष क्यों?

दरअसल, गठबंधन की राजनीति में सबसे बड़ा संकट सीटों की संख्या नहीं, विश्वास का

संकट होता है। यदि सपा को कांग्रेस पर और कांग्रेस को सपा पर भरोसा नहीं होगा तो कोई भी सीट समझौता स्थायी नहीं हो सकता। आज एक फार्मूला तय होगा, कल उम्मीदवार चयन पर विवाद होगा और चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल की समस्या सामने आएगी। ऐसी स्थिति में गठबंधन का लाभ विरोधी दल को मिल सकता है। इसलिए दोनों दलों को यह स्वीकार करना होगा कि गठबंधन में किसी एक दल की पूर्ण राजनीतिक संतुष्टि संभव नहीं होती। गठबंधन में समझौते करने पड़ते हैं। कुछ सीटें छोड़नी पड़ती हैं ताकि अधिक सीटें जीती जा सकें। राजनीति में कभी-कभी कम सीटों पर लड़ना, अधिक सीटें जीतने की रणनीति भी हो सकती है। इसके विपरीत अधिक सीटों पर लड़ने का अहंकार कई बार जीत की संभावनाओं को ही कमजोर कर देता है।

अखिलेश यादव का बात सीट की नहीं, जीत की है वाला कथन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें गठबंधन की राजनीति का मूल तत्व छिपा हुआ है। यदि सपा और कांग्रेस वास्तव में भाजपा को चुनौती देना चाहते हैं तो उन्हें अपने-अपने राजनीतिक विस्तार की चिंता के साथ-साथ साझा राजनीतिक लक्ष्य पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन कांग्रेस की चिंताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अपने संगठन और राजनीतिक प्रभाव को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। यदि वह लगातार अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहती है तो उसे सम्मानजनक सीट हिस्सेदारी की अपेक्षा स्वाभाविक रूप से होगी। दूसरी ओर सपा का तर्क यह हो सकता है कि जमीनी ताकत और चुनावी संभावना के आधार पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए। दोनों पक्षों की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। समाधान तभी निकलेगा जब दोनों दल अपनी मांगों को अंतिम सत्य मानने के बजाय जीत की संभावना को केंद्र में रखेंगे।

यह भी याद रखना होगा कि चुनाव केवल नेताओं का नहीं होता। चुनाव कार्यकर्ता लड़ते हैं। यदि सपा का कार्यकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी को और कांग्रेस का कार्यकर्ता सपा प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार स्वीकार नहीं करता तो गठबंधन का पूरा गणित बिगड़ सकता है। इसलिए सीट समझौते के साथ साझा चुनाव अभियान, संयुक्त सभाएं, स्पष्ट संदेश और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय भी जरूरी होगा।

आज देश की राजनीति में गठबंधन कोई

मुंशी प्रेमचंद



इस वजह से प्रेमचंद को सिनेजगत से अरुचि हो गई और वे 8 हजार रुपए वार्षिक आय को तिलांजलि देकर बंबई से काशी आ गए। फिल्म संसार से क्या मिला? इस सवाल के जवाब में प्रेमचंद लिखते हैं कि अंतिम समय उनके पास 1400

रुपए थे।

साहित्य का आदर्श- साहित्य की बात करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं- जो धन और संपत्ति चाहते हैं, साहित्य में उनके लिए स्थान नहीं है। केवल वे, जो यह विश्वास करते हैं कि सेवामय जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है, जो साहित्य के भक्त हैं और जिन्होंने अपने हृदय को समाज की पीड़ा और प्रेम की शक्ति से भर लिया है, उन्हीं के लिए साहित्य में स्थान है। वे ही समाज के ध्वज को लेकर आगे बढ़ने वाले सैनिक हैं।

संभावनाओं और मूल्यों को भी खोजने का प्रयास किया। इसी वजह से उनकी कहानियां व उपन्यास हिंदी साहित्य की अमर रचनाओं व कृतियों के रूप में अमिट थरोहर बन गईं।

प्रेमचंद आम आदमी तक अपने विचार पहुंचाकर उनकी सेवा करना चाहते थे। इसी मंशा से उन्होंने 1934 में अजंता सिनेटोन नामक फिल्म कंपनी से समझौता करके फिल्म- संसार में प्रवेश किया। वे बंबई पहुंचे और शेर दिल औरत और मिल मजदूर नामक दो कहानियां लिखीं। सेवा सदन को भी पढ़ें पर दिखाया गया। लेकिन प्रेमचंद मूलतः निकपट व्यक्ति थे।

फिल्म निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य जनता का पैसा लूटना था। उनका यह ध्येय नहीं था कि वे जनजीवन में परिवर्तन करें।

साहित्य व देश सबसे ऊपर- पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी की लिखे पत्र में प्रेमचंद ने कहा था- हमारी और कोई इच्छा नहीं है। इस समय यही अभिलाषा है कि स्वराज की लड़ाई में हमें जीतना चाहिए। मैं प्रसिद्धि या सौभाग्य की लालसा के पीछे नहीं हूँ। मैं किसी भी प्रकार से जिंदगी गुजार सकता हूँ।

मुझे कार और बंगले की कामना नहीं है लेकिन मैं तीन-चार अच्छी पुस्तकें लिखना चाहता हूँ, जिनमें स्वराज प्राप्ति की इच्छा का प्रतिपादन हो सके। मैं आलसी नहीं बन सकता। मैं साहित्य और अपने देश के लिए कुछ करने की आशा रखता हूँ। चांदनी जैसा निर्मल व्यक्तित्व- प्रेमचंद ने अपने जीवन में देशभक्ति, प्रामाणिकता और समाज सुधार का प्रचार न केवल अपनी लेखनी से किया, बल्कि वे जीवन में स्वयं उस पर चलते भी रहे।

आज का इतिहास

- 1936 ब्रिटिश टेलीविज़न प्रोग्राम पिक्चर का पहला एपिसोड प्रसारित किया गया।
- 1962 समचार पत्रिका डेर स्पीगेल ने पूर्व से साम्यवादी खतरे के खिलाफ पश्चिम जर्मन सशस्त्र बलों की असमानता का खुलासा किया, और कुछ ही समय बाद राजद्रोह के आरोपी थे।
- 1965 डाकघर टॉवर लंदन में खोला गया।
- 1967 मार्क्सवादी क्रांतिकारी और गुरिष्का नेता चे ग्वेरा को ला हिगुएरा, बोलीविया के पास हरा दिया गया।
- 1969 वेदर अंडरग्राउंड द्वारा आयोजित डेस्ट्रुक्शेन का आयोजन शिकागो में डेस्ट ऑफ रेज के नाम से जाना जाता है।
- 1973 ब्रिटेन का पहला स्वतंत्र रेडियो स्टेशन एलबीसी शुरू हुआ।
- 1973 एलबीसी रेडियो ने लंदन में 97.3 एएमपर पर प्रसारण शुरू किया।
- 1991 राष्ट्रपति बुश संघीय बैंकिंग नियमों में ढील देने के निर्णय पर पहुंच रहे हैं ताकि राष्ट्रों को कठिन ऋण परिस्थितियों के साथ कठिनाइयों को शांत करने में मदद मिल सके।
- 1996 ओटावा में आयोजित सम्मेलन में लगभग 50 देश बारूदी सुरंगों पर विश्वव्यापी प्रतिबंध लगाने पर सहमत हुए।
- 1998 नाँव के लिए मुख्य घरेलू केंद्र और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गार्डरमोनो हवाई अड्डा, ओस्लो हवाई अड्डे, फोरनेबू के रूप में खोला गया।
- 2000 वोजोस्लाव कोस्तुनिका यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति बने।
- 2001 अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू बुश ने होमलैंड सुरक्षा कार्यालय की स्थापना की।
- 2003 मिस वेनेजुएला गोजेदोर एजुआ ने टोक्यों में आयोजित मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता का खिताब जीता था।
- 2005 दक्षिण एशिया में आये एक भीषण भूकंप ने हज़ारों जानें ले लीं।
- 2008 हेर रंग के फ्लोरोसेंट प्रोटीन की खोज और विकास के लिए, ओोसामु शिमोमुरा, माट्टिन चॉली, और रोजर वाइस। फ़िस्एन को रसायन विज्ञान में 2008 का नोबेल पुरस्कार मिला।
- 2009 पोलिश राष्ट्रपति लेच काज़ींस्की ने शनिवार 10 अक्टूबर को लिस्बन संधि पर हस्ताक्षर करने के अपने इरादे की घोषणा की, जो देश की मंजूरी प्रक्रिया को पूरा करेगा।
- 2010 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 37 वीं विधानसभा मॉन्ट्रियल में शुक्रवार को समाप्त हो गई, जहां विमानन उत्सर्जन पर विकास किया गया था।
- 2011 शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने सूडान और दक्षिण सूडान के शरणार्थियों के लिए पश्चिमी इथियोपिया में एक नया शरणार्थी शिविर खोला।

क्या देश में मोदी विरोधी लहर शुरू हो चुकी है?

नीरज कुमार दुबे

आज जब नरेंद्र मोदी सरकार के मुखिया के रूप में लगातार पच्चीस साल पूरे कर रहे हैं, तब भारतीय राजनीति की एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण तस्वीर सामने आ रही है। सात अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सरकार की कमान संभालने वाले नरेंद्र मोदी ने पहले गुजरात और फिर देश की सत्ता का नेतृत्व करते हुए बिना किसी लंबे अंतराल के पच्चीस वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह अपने आप में भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की असाधारण राजनीतिक यात्रा है। इस अवसर पर सत्ता पक्ष इसे नेतृत्व, सेवा, विकास और निरंतर जनविश्वास की उपलब्धि के रूप में देख रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष ठीक इसी समय चुनावी संस्थाओं की विश्वसनीयता, मतदाता सूची और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर सरकार और चुनाव आयोग को घेर रहा है। यानी नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा के पच्चीसवें वर्ष का यह पड़ाव उस समय आया है जब सत्ता के सामने सबसे बड़ा सवाल शायद विपक्ष की ताकत का नहीं, बल्कि संस्थाओं और जनविश्वास का है।

देखा जाये तो सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन स्वाभाविक रूप से उपलब्धियों को गिाने का दिन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नरेंद्र मोदी के पच्चीस वर्ष के शासन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए उनके गुजरात के मुख्यमंत्रिव और केंद्र की तीन लगातार सरकारों को सार्वजनिक विश्वास का प्रमाण बताया है। सरकार की ओर से कल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचे, डिजिटल व्यवस्था, आर्थिक सुधार, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और तकनीकी उपलब्धियों को इस लंबे सफर की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी इस अवसर को सेवा और राष्ट्रहित के भाव से जोड़ा है।

लेकिन राजनीति सिर्फ उपलब्धियों की सूची से नहीं चलती। देश की राजनीति का दुहरा चेहरा भी उतनी ही ताकत से दिखाई दे रहा है। छह अक्टूबर को राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में प्रदर्शन किया। संसद से चुनाव आयोग की ओर बढ़ते विपक्षी सांसदों को पुलिस ने रोका, जिसके बाद धरना, हिरासत और राजनीतिक

टकराव की तस्वीरें सामने आईं। राहुल गांधी का बैरिकेड पर चढ़ना और अज्ञानेश, इट्स डन ब्रोड जैसी युवा शैली की भाषा सोशल मीडिया पर तेजी से फैली। इस पूरे बटनाक्रम ने चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विवाद को अचानक देश की राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया।

विपक्ष इस पूरे विवाद को केवल मतदाता सूची की तकनीकी प्रक्रिया नहीं मान रहा। उसके लिए यह लोकतंत्र, मताधिकार और चुनावी निष्पक्षता का सवाल है। कांग्रेस और उसके सहयोगी आरोप लगा रहे हैं कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने से नागरिकों के मतदान अधिकार पर असर पड़ सकता है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहा है और इस पूरे मामले को व्यापक राजनीतिक आंदोलन में बदलने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस लगातार चुनाव हारने के बाद चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा कर रही है और उसे अपनी राजनीतिक कमजोरी का जिम्मेदार संस्थाओं को बनाने के बजाय जनता का विश्वास जीतने की कोशिश करनी चाहिए। भाजपा का यह भी सवाल है कि जिस चुनावी व्यवस्था के माध्यम से विपक्ष कई राज्यों में जीत हासिल करता रहा, उसी व्यवस्था को अपनी हार के बाद अविश्वसनीय कैसे कहा जा सकता है।

यहीं से इस समय की राजनीति का सबसे बड़ा द्वंद्व सामने आता है। विपक्ष का सवाल है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न उठे तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा? सत्ता पक्ष का सवाल है कि बिना निर्णायक प्रमाण के चुनावी व्यवस्था को कठघरे में खड़ा करने से क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा ही कमजोर नहीं होगा? दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क रख रहे हैं, लेकिन एक तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर बहस अब महज विपक्षी भाषण नहीं रह गई है। हालांकि इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि विपक्ष के सारे आरोप सिद्ध हो चुके हैं। चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठना एक बात है और चुनाव चोरी सिद्ध हो जाना दूसरी बात है।

शायद यही वह बिंदु है जहां से आम जनता और राजनीतिक विमर्श के बीच अंतर दिखाई देता है। राजनीति की दुनिया में इस समय झुद्ध चुनाव आयोग



और ज्ञानेश कुमार सबसे बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहे हैं। समाचार चैनलों और सोशल मीडिया पर भी यही सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम व्यापक जनमत संकेतकों को देखते हैं तो तस्वीर कुछ अलग है। सितंबर 2026 के ताजा इप्सास सर्वेक्षण में सात में से लगभग सात भारतीयों ने माना कि देश सही दिशा में जा रहा है और करीब आठ में से आठ ने वर्तमान आर्थिक स्थिति को सकारात्मक माना है। लेकिन उसी सर्वेक्षण में बेरोजगारी भारत की सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। यानी देश के भविष्य को लेकर आशावाद मौजूद है, मगर नौकरी और अवसर को लेकर बेचैनी भी उतनी ही वास्तविक है।

यही भारतीय जनमत की वर्तमान जटिलता है। जनता का एक बड़ा हिस्सा यह मान सकता है कि देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था टिकाऊ है, बुनियादी ढांचे में बदलाव आया है और भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई है, लेकिन उसी व्यक्ति के घर में नौकरी, आमदनी, महंगाई और भविष्य की सुरक्षा की चिंता भी हो सकती है। सितंबर में शहरी उपभोक्ता विश्वास में भी सुधार आया और भारत का उपभोक्ता विश्वास सूचकांक बढ़ा। इसका मतलब यह हुआ कि आर्थिक तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक नहीं है; फिर भी रोजगार सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है।

इससे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के सामने असली राजनीतिक प्रश्न भी स्पष्ट होता है। चुनौती केवल यह नहीं है कि विपक्ष किना आक्रामक है। चुनौती यह है कि सरकार आर्थिक उपलब्धियों और बड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों की कथा को आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी से कितना जोड़ पाती है। जब विकास का अर्थ सड़क, रेल, डिजिटल भुगतान और वैश्विक प्रतिष्ठा से आगे बढ़कर

अवधेश कुमार

देश फिर आंदोलन की चपेट में है।

पहले तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग थी, तो अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के। पिछले आंदोलन में जंतर-मंतर से निकलकर हजारों की संख्या में पुलिस बैरिकेड तोड़ते हुए समूह उग्र तेवर के साथ संसद भवन तक पहुंच गया था। पुलिस के सामने संसद भवन की सुरक्षा की चुनौती थी।

यह स्थिति पहली बार नहीं हुई है। हाल के वर्षों में सारे आंदोलनों में अराजक हिंसा के दृश्य हमने देखे हैं। कृषि कानूनों को लेकर धरना और आंदोलन इतना अराजक व हिंसक हुआ कि प्रदर्शनकारी लाल किले पर चढ़ गए, तिरंगा उतारकर दूसरा झंडा लगा दिया। हालिया जंतर-मंतर आंदोलन में भी पुलिस की गाड़ियों को उलटना, तोड़ना, घेरकर पीटना और पत्थरबाजी भी प्रदर्शन के भाग थे। अग्निवीर योजना के विरुद्ध हुए आंदोलन में भी जबर्दस्त हिंसा हुई। मसलन, बिहार में कुछ नेताओं के घरों पर हमले हुए, ट्रैन, बस और थाने तक जले। क्या आंदोलनों का यह चरित्र डराता नहीं है? देश का दुर्भाग्य है कि राजनीतिक दलों में भी दूरदृष्टि, विवेक और देश के भविष्य को ध्यान में रखकर सोचने वालों की संख्या बेहद कम है। जो हैं भी, वे अक्सर पार्टी में प्रभावी भूमिका में नहीं हैं। इसलिए, पार्टियां या तो मौन रहतीं हैं या सिर्फ दमन और अत्याचार जैसे मुहानों का

नौकरी, स्थिर आय और युवा के भविष्य में दिखाई देने लगेगा, तभी सरकारी उपलब्धियों का राजनीतिक असर और गहरा होगा।

साथ ही नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत नेतृत्व को लेकर तस्वीर अभी भी पूरी तरह बदलती हुई नहीं दिखती। अगस्त 2026 के इंडिया टुडे-सी वोटर सर्वेक्षण में 48.7 प्रतिशत लोगों ने मोदी को अगले प्रधानमंत्री के लिए सबसे पसंदीदा विकल्प माना। हालांकि जनवरी के मुकाबले उनके समर्थन में कुछ कमी आई है। इस गिरावट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे सीधे मोदी विरोधी लहर भी नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर, राहुल गांधी अभी तक उस राजनीतिक बढ़त को हासिल नहीं कर पाए हैं, जो मोदी के समर्थन में कमी आने पर उन्हें स्वाभाविक रूप से मिल सकती थी। यानी मोदी की राजनीतिक ताकत अभी भी बनी हुई है, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहा है। पहले मोदी को लेकर बहस अक्सर इस बात पर केंद्रित रहती थी कि उनके मुकाबले कौन है? अब बहस का एक हिस्सा इस बात पर भी केंद्रित होने लगा है कि सरकार और संवैधानिक संस्थाएं जनता का विश्वास कितना कायम रख पा रही हैं? यही बदलाव आगे चलकर महत्वपूर्ण हो सकता है।

सोशल मीडिया पर भी इस समय राजनीति का यही दोहरा चेहरा दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी के प्रदर्शन के वीडियो और उनके अंदाज को उनके समर्थक पसंद कर रहे हैं, जबकि विरोधी इसे राजनीतिक दिखावा बता रहे हैं। भाजपा भी सोशल मीडिया के जरिए इसका जवाब दे रही है। यानी सोशल मीडिया ने राजनीतिक बहस को जरूर ज्यादा तेज और आक्रामक बना दिया है, लेकिन वहां दिखाई देने वाली प्रतिक्रियाओं को पूरे देश की राय मान लेना ठीक नहीं होगा। सोशल मीडिया पर वही आवाज ज्यादा सुनाई देती है, जिसके पीछे बड़ी संख्या में सक्रिय और भावनात्मक समर्थक हों। इसलिए सोशल मीडिया का शोर यह तो बताता है कि किसी मुद्दे पर बहस कितीनी तेज है, लेकिन यह नहीं बताता कि जनता का बड़ा हिस्सा वास्तव में क्या सोच रहा है।

इस पूरे परिदृश्य में युवाओं की बेचैनी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कॉर्कोरोच जनता पार्टी जैसे युवा केंद्रित आंदोलनों और उनसे जुड़ी डिजिटल राजनीति ने यह दिखाया है कि एक नया

क्यों इतने अधिक लोकप्रिय हैं विदेश मंत्री जयशंकर?

हरीश गुप्ता

यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सच है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से विदेश मंत्रालय को अन्य मंत्रालयों की तुलना में अधिक महत्व प्राप्त हो गया है। मोदी नियमित रूप से विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों और सचिवों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकें करते हैं और उनसे उनके प्रदर्शन, लक्ष्यों और समयसीमाओं के बारे में गहन पूछताछ करते हैं।

जबकि विदेश मंत्रालय इन सामूहिक समीक्षा बैठकों से काफी हद तक बाहर ही रहा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि विदेश नीति का महत्व कम हो गया है। बल्कि इसके विपरीत, यह प्रधानमंत्री की विदेश मामलों पर सीधे और बेहद करीबी नियंत्रण बनाए रखने की प्राथमिकता को दर्शाता है।

विदेश नीति का संचालन विदेश मंत्री एस। जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिसरी सहित अनुभवी राजनयिकों द्वारा प्रतिदित किया जाता है। लेकिन मोदी स्वयं औपचारिक तंत्रों के साथ-साथ प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से भी इस पर कड़ी नजर रखते हैं। सरकार के कामकाज से परिचित लोगों का कहना है कि मोदी और जयशंकर लगातार संपर्क में रहते हैं और अक्सर तात्कालिक मुद्दों पर दिन में कई बार बात करते हैं।

विदेश सचिव को भी नियमित रूप से इस पूरी प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। बुनियादी ढांचे, संपर्क और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के सामने आने पर विदेश मंत्रालय की जांच-पड़ताल और भी कड़ी



हो जाती है। उदाहरण के लिए, चाबहार बंदरगाह को ही लें।

हालांकि बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्रालय परिकलान पक्ष संभालता है, लेकिन ईरान के साथ बातचीत और रणनीतिक जुड़ाव में विदेश मंत्रालय की भूमिका अनिवार्य रूप से सामने आ जाती है। दूसरे, विदेश मंत्रालय मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह समिति बड़े रणनीतिक, विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेती है।

जयशंकर का महत्व विदेश मंत्री की पारंपरिक भूमिका से कहीं अधिक है। वे वस्तुतः 24x7 मंत्री हैं, जिनका एक पैर दिल्ली में और दूसरा लगातार विदेशी धरती पर रहता है। पूर्व राजनयिक जयशंकर दृढ़, स्पष्टवादी और बेबाक हैं। भले ही वे कूटनीतिक अगत से आए हों, लेकिन स्पष्ट बोलने की जरूरत पड़ने पर वे जरा भी संकोच नहीं करते।

खरे सिक्कों को चुकानी पड़ती है खोटे सिक्कों की कीमत!

हेमधर शर्मा

पिछले दिनों पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने दावा किया कि गिरफ्तार संदिग्ध जैश-ए-मोहम्मद ऑपरेटिव हमीम मंडल ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छत्र प्रदर्शन में पुलिस की वर्दी पहन कर घुसपैठ और तोड़फोड़ की साजिश रची थी। जाहिर है कि हमीम का मकसद पुलिस की वर्दी को बदनाम करना था। लेकिन असामाजिक तत्व सिर्फ पुलिस की वर्दी का ही इस्तेमाल नहीं कर रहे। जेन-जी के दुनियाभर में हो रहे आंदोलनों में भी घुसकर वे तोड़फोड़ मचाते हुए हिंसा कर रहे हैं। नेपाल में हुए जेन-जी के आंदोलन में जब संसद और सुप्रीम कोर्ट को इमरत जैसे संवैधानिक स्थलों को ढहा दिया गया तो बहुत से युवा सदमे में आ गए थे कि उनके आंदोलन ने यह क्या कर डाला। बांग्लादेश में भी छात्रों के आंदोलन को कट्टरपंथियों ने हड़प लिया था और छात्रों को लगता रहा कि उनके बीच के ही लोग यह सब कर रहे हैं।

वर्तमान दौर के आंदोलनों की सबसे खतरनाक बात यही है कि आंदोलनकारी समझ ही नहीं पाते कि उनके सहयोगियों का वेश बनाकर असामाजिक तत्व भी आंदोलन में घुस आए हैं और उसका अपने निहित स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आंदोलन की अनुवाई करने वाले लोग असामाजिक तत्वों को अपना समझ कर उनके हिंसक कृत्यों का बचाव करने लगते हैं, नतीजतन आंदोलन अपने उद्देश्य से भटक जाता है। लेकिन यह हथ्र क्या सिर्फ आंदोलन का ही हो रहा है? जीवन का शायद कोई भी क्षे्र ऐसा नहीं बचा है जहां खरे सिक्कों के वेश में खोटे सिक्के हावी होने की कोशिश न कर रहे हों। जिस तरह जरा सा भी मीठा कहीं दिखा नहीं कि चींटियां उसे हजम करने को टूट पड़ती हैं,

उसी तरह जहां भी कुछ खरापन दिखा नहीं कि खोटापन उसे दीमक की भाँति चाटने को आतुर हो जाता



है। झूठ आज अपने मुखौटे को इतना परिष्कृत करने में लगा हुआ है कि सच को पहचानना बेहद कठिन हो चला है; ठीक वैसे ही जैसे एआई के डीप फेक और असलियत में फर्क कर पाना असंभव की हद तक मुश्किल होता जा रहा है।

लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि झूठ की कीमत सच को किस तरह चुकानी पड़ती है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 22 साल तक जेल की सजा काटने वाले एक ऐसे व्यक्ति को निर्दोष बरी किया, जिस पर तीन महिलाओं की हत्या का मुकदमा चला था। लेकिन बरी होने के बाद जब वह घर लौटा तो देखा कि परिवार में कोई जिंदा नहीं बचा है।

अब वह बदहवास इधर-उधर भटकता है, अक्सर नदी किनारे गुमसुम बैठा रहता है, जैसे समझ में ही न आ रहा हो कि क्या करे! तीन महिलाओं की हत्या का दोषी निश्चित रूप से कोई न कोई तो होगा ही, लेकिन वह आजाद घूम रहा होगा क्योंकि उसके हिस्से की सजा किसी निर्दोष ने भुगत ली है! खोटे सिक्के इसी तरह खरे सिक्कों की बलि लेते हैं।

यह सिलसिला कोई आज का नहीं है। टॉलस्टॉय की मशहूर कहानी है जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति जीवनभर हत्या की सजा भुगतता है और अंत में एक व्यक्ति द्वारा जुर्म

कबूलने पर सत्ता चलता है कि हत्यारा तो कोई और है! हिंदी साहित्यकार पुरंदरशन की कहानी 'हार की जीत' में बाबा भारती की मानवता आखिर डाकू खड्ग सिंह को दुष्टता पर जीत हासिल कर लेती है।

अब कुछ सी साल के भीतर ही हमारा समाज क्या इतना बदल चुका है कि अपराधियों के हृदय परिवर्तन की जरा भी उम्मीद नजर नहीं आती? यह सच है कि अंग्रेजिमाल जैसे खूंखार लुटेरे का कार्यांतरण गौतम बुद्ध जैसे करुणावान महापुरुष ही कर सकते हैं। जो आग कचरे को जला डालती है, वही सोने को दमका कर कुंदन बनाती है।

आज के खूंखार अपराधियों को बदल पाना भी असंभव नहीं है, लेकिन जितना वे बुराई के क्षेत्र में आगे हैं, उतना ही उन्हें सुधारने की इच्छा रखने वालों को अच्छाई के क्षेत्र में ऊंचाई हासिल करनी होगी। जैसा कि अहिंसा के बारे में गांधीजी कहते थे कि दूसरों की जान लेने का जितना दुस्साहस हिंसक लोगों के पास होता है,

अपनी जान देने का उतना ही साहस जब तक अहिंसक लोग हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक अहिंसा की सफलता की उम्मीद नहीं की जा सकती। खुद को शरीफ मानने वाले हम सभी लोगों को अपने भीतर झांक कर देखना होगा कि अपने ध्येय के प्रति क्या हम भी बुरे लोगों जितनी ही निष्ठा रखते हैं? साथ ही यह तसल्ली भी कर लेनी होगी कि क्या हम सचमुच ही अच्छाई के पक्ष में हैं, कहीं अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे? आखिर पेपर लोक के मास्टरमाइंड भी तो कई बार वही निकलते हैं जिन पर प्रश्नपत्र बनाने की प्रक्रिया की जिम्मेदारी होती है!

कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ तो हम नींद पेपर लोक के खिलाफ आंदोलन में शामिल हो रहे हों और दूसरी तरफ मौका मिलते ही पेपर लोक कर अपना स्वार्थ भी साध रहे हों? आखिर जिन्हें हम खोटा सिका समझते हैं, वे भी अपने आप को खरा होने का भुलावा देने की कोशिश तो करते ही होंगे!



उपयोग कर छुट्टी पा लेती हैं।

वास्तव में हम एक ऐसे डरावने दौर में

हैं, जहां से जितना आगे बढ़ेंगे, उतना अनर्थ होगा। लोकतंत्र में किसी को भी धरना-प्रदर्शन और आंदोलन करने का अधिकार है। सत्ता अथवा किसी स्तर पर कोई फैसला या कार्रवाई जनविरोधी या अन्यायपूर्ण है, तो उसके प्रतिकार का रास्ता हमें अतीत से अहिंसक आंदोलनों के रूप में मिला है। लेकिन, इनकी मर्यादा और गरिमा रही है। आजकल सभी महात्मा गांधी से लेकर जयप्रकाश नारायण (जेपी) का नाम लेते हैं। तिरंगा और सविधान लहराते हैं, पर क्या गांधीजी की भाषा का मर्म आत्मसात करते हैं? जयप्रकाश जी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध छात्र आंदोलन के नेतृत्व का दायित्व लिया, तो छात्र नेताओं से लिखवाया कि वे हिंसा न करने के साथ अभद्र और उग्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। गांधीजी ने चौरी-चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। जयप्रकाश जी ने नारा भी दिया था-

‘चाहे चले लाठी-गोलियां, हाथ हमारा नहीं उठेगा।' इन महापुरुषों के लिए साध्य और साधन, दोनों की पवित्रता सर्वोच्च मायने रखती थी। आज की भाषा में हिंसा, उग्रता और अभद्रता स्पष्ट दिखती है। जैसे नारे लगते हैं या पोस्टर दिखाए जाते हैं, वैसी भाषा व उग्रता अकल्पनीय है। वास्तविक आंदोलनकारी-सत्याग्रही, अपनी मांग को लेकर धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पर कभी अराजकता की सीमा तक नहीं पहुंचते। अब तो ऐसा लगता है, मानो आंदोलन नहीं, युद्ध के मोर्चे में उतरे हैं।

प्रश्न है कि ऐसी स्थिति पैदा हुई क्यों? जब भी कोई आंदोलन हिंसक हो, उसमें अवांछित तत्वों की भूमिका की पुष्टि हो जाए, तो प्रशासन का दायित्व है कि बिना देर किए उसे कठोरता से नियंत्रित करे। नहीं तो, अराजक तत्व उसे उग्रवादी और हिंसक बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोग श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश और नेपाल तक के उग्र हिंसक आंदोलनों की परिणतियों को मिसाल बनाने में लगे हैं। एक नेता का बयान भी था कि 'हमसे गलती हो गई, ट्रैक्टर परेड के दिन ही हम संसद तक चले जाते और बांग्लादेश दोहरा देते।' इस तरह की अतिवादी मानसिकता सामान्य मानी जाने लगी है, जिससे निहित स्वार्थी तत्वों को मौका मिल जाता है।

एक विचित्र पैटर्न देखने में आता है-

पहले धरना शुरू होता है, फिर सड़क घेर ली जाती है और कुछ स्थायी निर्माण भी हो जाते हैं। अंततः दंगे की स्थिति बन जाती है। ऐसे में, शेष नागरिकों के अधिकारों का क्या? देश की राजधानी की नाकेबंदी और जनता में दहशत का माहौल बने, इससे पहले ही प्रशासनिक प्रयास क्यों नहीं होते? एक आंदोलन के वक्त तो पूरी दिल्ली हलकान हो गई थी, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कच्चे माल व सामग्रियों की आपूर्ति का संकट पैदा हो गया था, लोग त्राहि-त्राहि करते रहे, पर कार्रवाई नहीं हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी को केंद्र बनाकर अमेरिका से अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर कॉर्कोरोच जनता पार्टी का गठन किया, तो किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। यहां तक कि जंतर-मंतर पर पहले से धरने की अनुमति भी नहीं थी। दिल्ली पुलिस ने त्वरित अनुमति दी। आगे चलकर प्रशासनिक हल्केपन से अराजक, अवांछित तत्वों को भी इसकी आड़ में मौका मिल गया। आज लंबे समय से निष्क्रिय, छटपटाते लोगों के लिए भी इस बैनर के नाम पर एक माध्यम मिल गया है।

कानून व्यवस्था और देश में शांति व स्थिरता प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। समग्र रूप से विचार कर इस प्रवृत्ति को नहीं रोका गया, तो अराजक तत्वों का आंदोलनों में प्रवेश सामान्य हो जाएगा और फिर हिंसा को एक सीमा के बाद रोकना निहायत मुश्किल होगा।

भीतरघात से जूझ रहे महाविकास अघाड़ी और महायुति, निर्दलीय बिगाड़ेंगे खेल?

नितिन गौतम

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों के भीतर बगावत सामने आई है। 23 अक्टूबर को होने वाले पांच सीटों के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की समयसीमा मंगलवार को खत्म होने के साथ ही कई दावेदारों ने अपनी ही पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ पर्चा दाखिल कर दिया। गठबंधन स्तर पर भी सहयोगी दलों ने एक-दूसरे के हिस्से की सीटों पर दावेदारी जताते हुए उम्मीदवार उतारे हैं। इन चुनावों में विधान परिषद की तीन स्नातक और दो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों पर मतदान होगा। इनमें पुणे संभाग स्नातक, नागपुर संभाग स्नातक, पुणे संभाग शिक्षक, छत्रपति संभाजीनगर स्नातक और अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। सत्तारूढ़ महायुति में भाजपा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और एनसीपी शामिल हैं, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी शरदचंद्र पवार और शिवसेना यूबीटी शामिल हैं।नागपुर स्नातक सीट पर कांग्रेस ने मौजूदा एमएलसी अभिजीत वंजारी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने सुधाकर कोहले को मैदान में उतारा है। हालांकि, भाजपा के पूर्व एमएलसी और नेता अनिल सोले ने टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। अमरावती शिक्षक सीट पर कांग्रेस ने अदिति पोहारे को उम्मीदवार बनाया है, जबकि महायुति ने शिवसेना के मौजूदा एमएलसी किरण सरनाईक को टिकट दिया है। वहीं, कांग्रेस के उम्मीदवार के बावजूद शिवसेना यूबीटी ने

राजनीतिक असंतोष उभर रहा है जो जरूरी नहीं कि सीधे कांग्रेस या भाजपा की पारंपरिक राजनीति में समा जाए। रोजगार, परीक्षा व्यवस्था, अवसर और संस्थायत निष्पक्षता जैसे मुद्दे इस नई पीढ़ी को प्रभावित कर रहे हैं। यह नाराजगी अभी किसी एक पार्टी के पक्ष में संगठित नहीं हुई है, लेकिन इसे हल्के में लेना भी उचित नहीं होगा।

इसलिए आज की भारतीय राजनीति को अगर एक वाक्य में समझना हो तो तस्वीर यह है कि नरेंद्र मोदी का जनाधार टूटा नहीं है, मगर उनके नेतृत्व के इर्द-गिर्द सवालों की प्रकृति बदल रही है। व्यक्तिगत लोकप्रियता अभी मजबूत है, सरकार की उपलब्धियों का नैरेटिव अभी जीवित और प्रभावी है, देश की आर्थिक दिशा को लेकर आशावाद भी मौजूद है; लेकिन रोजगार की चिंता, युवा असंतोष और चुनावी संस्थाओं की विश्वसनीयता पर उठते सवाल एक नया दबाव पैदा कर रहे हैं। मोदी के लिए असली चुनौती विपक्ष की किसी एक रैली से नहीं, बल्कि इन अलग-अलग चिंताओं के एक साथ जुड़ जाने से पैदा हो सकती है।

फिलहाल स्थिति को मोदी विरोधी लहर कहना अतिशयोक्ति होगी। लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि जनता के भीतर कोई बेचैनी नहीं है। बेचैनी है, सवाल हैं, संस्थाओं को लेकर आशंका है और युवाओं में अवसर को लेकर अधीरता है। साथ ही देश के बड़े हिस्से में स्थिरता, आर्थिक दिशा और प्रधानमंत्री के नेतृत्व को लेकर भरोसा भी कायम है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय मतदाता इस समय न तो पूरी तरह नाराज होकर सत्ता से विमुख दिखाई दे रहा है और न ही आखें बंद करके संतुष्ट है। यही नरेंद्र मोदी के पच्चीसवें वर्ष की सबसे बड़ी राजनीतिक सच्चाई है। यहां यह भी सवाल उठता है कि देश में आज चुनाव हों तो क्या होगा? उपलब्ध ताजा राष्ट्रीय जनमत संकेतक सरकार के लिए चेतावनी जरूर देते हैं लेकिन उसके लिए खतरे का संकेत नहीं दे रहे। अगस्त 2026 के इंडिया टुडे-सी वोटर सर्वेक्षण के मुताबिक आज लोकसभा चुनाव होने पर भाजपा को 261 और एनडीए को 326 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन 185 सीटों तक पहुंच सकता है। यानी भाजपा अपने दम पर बहुमत से नीचे रहेगी, लेकिन एनडीए फिर भी आराम से सरकार बनाने की स्थिति में रहेगा।



बॉस हों पार्ट टाइमर तो ऐसे करें डील

वह पावर का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। बॉस का पद जिम्मेदारी भरा पद होता है और कंपनी बॉस पर भी नजर रखती है। याद रखें कि इसके लिए कंपनी हमेशा ही अपने स्तर पर सही व्यक्ति का चुनाव करती है। ऐसे में यह है कि टीम भी सही मानसिकता के साथ बॉस को सहयोग दे और अपना काम करे। वह कॉरपोरेट जगत के वैल्यू को समझे।

कम्यूनिकेशन का होता है अहम रोल

जहां बॉस पार्ट टाइमर काम करते हैं और उनके साथ काम करने वाले बाकी लोग फुल टाइम

जॉब करते हैं, वहां पर कम्यूनिकेशन का रोल अहम हो जाता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसी स्थिति में टीम को बॉस के साथ कम्यूनिकेशन लेवल हाई रखना पड़ता है। एक बार कम्यूनिकेशन करने का स्टाइल फिक्स हो जाता है, तो बाद में चीजों को बदल पाना आसान नहीं होता है। जब कम्यूनिकेशन सही रहेगा तो प्रॉब्लम का निपटारा भी पलक झपकते ही हो जाएगा। ऐसे में पार्ट टाइमर बॉस के संग भी टीम बेहतर रिजल्ट दे सकती है।

फैसला लेने की कला सीखें

आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं, जहां फुल

टाइमर बॉस नहीं हैं, तो जरूरी है कि टीम का हर एक सदस्य खुद पर भरोसा दिखाए और फैसला लेने की कला सीखे। याद रखें कि जब बॉस फुल टाइमर नहीं होते हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत फैसला लेने में ही होती है। वर्कप्लेस पर कई बार आपको पलक झपकते ही बड़े फैसले लेने होते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा यह होता है कि आप आज के कॉम्पिटिशन भरे माहौल में टीम में तेजी कैसे लाएं। जब एक्सपर्ट कहते हैं कि इससे निपटने के लिए कंपनियों को चाहिए कि वह फैसला लेने के अधिकार को बांट दे। इससे जहां टीम के सदस्यों में कॉन्फिडेंस पैदा होता है, वहीं समय के भीतर फैसला लेने से काम में तेजी भी आती है।

...तो आप भी हैं कामयाब लीडर

एक लीडर में अपनी बात को असरदार तरीके से दूसरों तक पहुंचाने का हुनर आना चाहिए। एक लीडर, अगर वह अपनी बात अपने साथ काम करने वालों को बेहतर तरीके से कम्यूनिकेट कर पाने में समर्थ है, तो इससे कामकाजी माहौल ऊर्जा से भर जाता है, लोग उत्साह से काम में जुटते हैं और उनकी रचनात्मकता काम में झलकने लगती है। एक दूरदर्शी सोच रखने वाला लीडर एक जुनूनी टीम बनाने में यकीन रखता है। यह टीम एक समान लक्ष्यों के लिए पूरे जोशोखरोश से काम करती है। अपना कारोबार फैलाती किसी भी कंपनी को एक मजबूत मैनेजमेंट के साथ-साथ ऐसी टीम की भी दरकार रहती है, जो साथ काम करने वाले लोगों के बीच आपसी एकता, यकीन और आदर की बुनियाद पर बनी हो। कामयाबी का राज है, कामकाज में साफ-सुथरापन। एक कामयाब लीडर इस बात की अहमियत जानता है और अच्छे कामकाज के लिए अपने एंग्लोई के साथ एक बेहतर समझ विकसित करता है। इससे न सिर्फ कामकाज का बिना किसी रुकावट के निपटारा होता जाता है, बल्कि टीम के भीतर एक खुशनुमा कामकाजी माहौल भी बरकरार रहता है।

जॉब के दौरान कई परिस्थितियों से दो चार होना पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि कंपनी पार्ट टाइम बॉस को नियुक्त कर दे। ऐसी स्थिति में टीम की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बॉस के साथ तालमेल बैठाकर उन्हें फैसले लेने होते हैं...

जब आपके ऑफिस में पार्ट टाइमर काम करने वाले बॉस हों और आप फुल टाइमर एम्प्लॉई हों, तो स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो जाती है। ऐसे में पूरी टीम को बॉस के साथ बराबर टच में रहना होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीम को फुल टाइमर बॉस की कमी महसूस होती है। टीम को कई मुद्दों पर बातचीत करने की जरूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि पार्ट टाइमर बॉस पूरा समय नहीं दे पाते हैं। आप अपनी कंपनी में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो यहां पर दिए जाने वाले टिप्स कारगर साबित हो सकते हैं। आइए डालते हैं एक नजर –

मानसिकता सही रखें

एक्सपर्ट कहते हैं कि एक पार्ट टाइमर बॉस किसी संस्था में काम करता है, तो वहां पर काम करने वाले लोगों के मन में यह भावना विकसित हो सकती है कि



इन बातों का ध्यान रखें तो कदम चूमेगी कामयाबी

जब आप अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट होते हैं, तो यह जान जाते हैं कि आप कौन हैं? आप क्या हैं? आपको क्या करना है और आप क्या चाहते हैं? अगर ये चीजें आपके दिमाग में साफ हैं, तो आपकी सफलता का पहला चरण सुनिश्चित हो जाता है।

बनें योग्य

कामयाब होने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप खुद को योग्य बनाएं। क्योंकि आप तब तक ऊपर नहीं चढ़ सकते, जब तक कि आप में योग्यता नहीं हो। इसलिए पहले खुद को योग्य बनाना जरूरी होता है। इसके लिए लगातार प्रयत्न करना पड़ेगा। याद रखें कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है।

दबाव झेलने की क्षमता

जब जिम्मेदारी बढ़ेगी तो दबाव के साथ-साथ अवरोध भी उत्पन्न होगा। ऐसे में इस तरह की विपरीत परिस्थितियों को झेलने की क्षमता आपमें जरूर होनी चाहिए। वैसे जब आपको एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी हो तो रास्ते में दिक्कतें तो आएंगी ही।

दिक्कतों का सामना करने से ही सफलता का दरवाजा खुलता है।

भरपूर एकाग्रता जरूरी

इसके बिना तो आप साइकल भी नहीं चला सकते। एकाग्रता एक ऐसी चीज है, जो हर जगह काम आती है। आप अपने काम में इसके द्वारा ही परफेक्शन लाते हैं। किसी भी काम को साधारण से असाधारण बनाने के लिए एकाग्रता की जरूरत होती है। इसके माध्यम से आप बड़े से बड़े लक्ष्य को भेद सकते हैं।

रचनात्मकता भी जरूरी

एक प्रफेशनल की सफलता में उसकी रचनात्मकता का काफी अहम योगदान होता है। इसलिए इस ओर ध्यान देना जरूरी है।

साहस बनाए रखें

कहते हैं रिस्क लेने के बाद ही आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है। इसके लिए साहस सबसे जरूरी चीज है। किसी ने सही कहा है कि हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती इसलिए जीतने के लिए साहस बहुत जरूरी है।



हार्डवेयर फील्ड में खूब हैं जॉब, मस्त सैलरी

आज शायद ही ऐसा कोई ऑफिस हो, जहां का कामकाज कंप्यूटर पर आधारित न हो। इसके अलावा, घर, स्कूल आदि जगहों पर भी सभी कामकाज कंप्यूटर पर ही किए जाते हैं। अगर ये सुचारू रूप से काम न करें, तो सारा कामकाज अचानक ठप हो सकता है। बैंकों और अन्य सरकारी कार्यालयों में नेटवर्क फेल होने की वजह से काम ठप रहने की खबरें आपने अक्सर पढ़ी होंगी, तब इस नेटवर्क को सही करने के लिए हार्डवेयर प्रफेशनल्स की ही मदद ली जाती है। नेटवर्किंग दरअसल कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर ऐसा जाल बनाने का फील्ड है जिसमें कोई संस्थान काम कर सके। कुल मिलाकर, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन से लेकर, इसकी मॉटेनेंस और रीजमररी के ऐडमिनिस्ट्रेशन तक का सारा जिम्मा कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट्स यानी हार्डवेयर इंजिनियर्स के जिम्मे होता है।

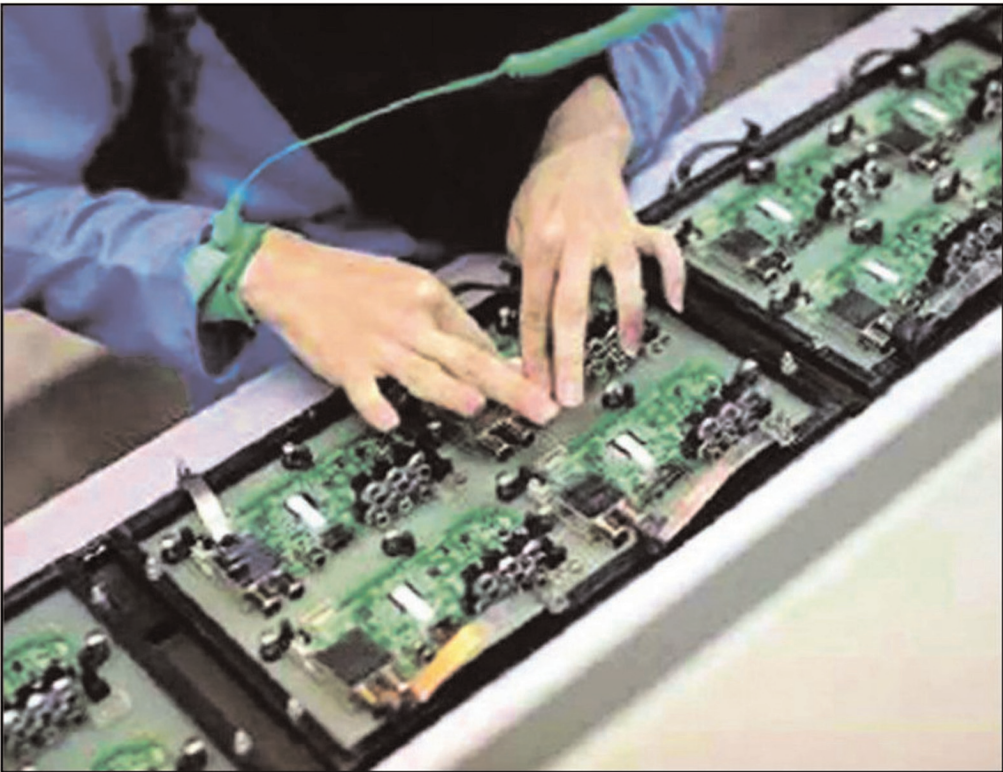
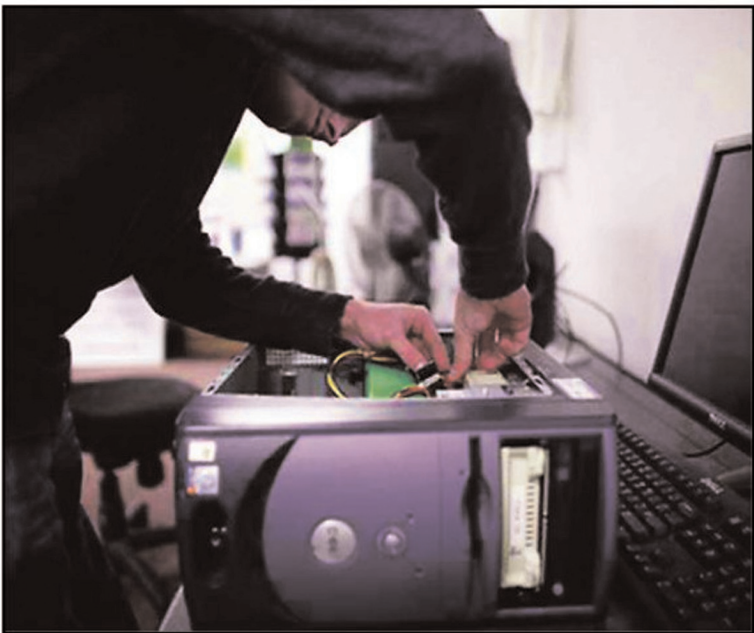
कोर्स

हार्डवेयर इंजिनियर बनने के लिए मुख्य रूप से दो बेसिक कोर्स करने पड़ते हैं। पहला, हार्डवेयर और दूसरा बेसिक नेटवर्किंग। हार्डवेयर रिलेटिड कोर्स से कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में तमाम तकनीकी जानकारी मिलती है। एक हार्डवेयर इंजिनियर या सिस्टम ऐडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए ये दोनों कोर्स करने बेहद जरूरी हैं। नेटवर्किंग में इससे आगे कोई एक्सपर्ट बनना हो, तो अपनी पसंद के हिसाब से कुछ और बेसिक कोर्स करने होंगे, जैसे - लैन (लोकल एरिया नेटवर्क) और वैन (वाइड एरिया नेटवर्क) से

जुड़े कोर्स। नेटवर्किंग से जुड़े कोर्स कराने के लिए कई सरकारी और प्राइवेट संस्थान हैं, जिन्होंने इन कोर्सज के लिए अपनी अलग पहचान बनाई है। नेटवर्किंग सीखने के लिए तीन तरीके हैं - पहला ऑनलाइन स्टडी मटेरियल की मदद से खुद पढ़ाई, दूसरा ऐसे इंस्टिट्यूट्स जो किसी प्रोग्राम से जुड़े नहीं हैं और तीसरा सर्टिफाइड प्रोग्राम।

जॉब की कमी नहीं

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि नेटवर्किंग में कोर्स करने के बाद कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट, हेल्प डेस्क टेक्निशियन, नेटवर्क या सिस्टम ऐडमिनिस्ट्रेटर, कंप्यूटर सिस्टेम्स इंजीनियर



स्पेशलिस्ट के रूप में करियर बना सकते हैं। आज इन एक्सपर्ट्स की जरूरत लगभग हर संस्थान में होती है। फिर चाहे वह कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग युनिट हों, बैंक या अन्य सरकारी कार्यालय, कोई इंडस्ट्री या और कोई छोटी-बड़ी फर्म। जहां भी कामकाज कंप्यूटर आधारित है, वहां इन तकनीकी विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। सरकारें जिस तरह ई-गवर्नेंस पर जोर दे रही हैं, उससे यह फील्ड और भी हॉट बनता जा रहा है। इसके चलते स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क और डाटा सेंटर जैसे कई नए फील्ड खुल रहे हैं। कहा जा सकता है कि जब तक कंप्यूटर पर काम होता रहेगा, इन विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती रहेगी। ये किसी भी कंपनी के लिए नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम की देखभाल से लेकर, एंफ्लायीज और करंट मर्स की तकनीकी जिज्ञासाओं को शांत करने तक का काम करते हैं। एंटी लेवल पर आपकी जिम्मेदारी केवल नेटवर्क और कंप्यूटर मॉटेनेंस की हो सकती है, लेकिन अनुभव के साथ आपको किसी कंपनी के लिए इंटरनेट आदि डिजिटल करने का जिम्मा भी दिया जा सकता है।

मनी मैटर्स

बरसों से आईटी फील्ड में अच्छी-खासी सैलरी रही है। हार्डवेयर प्रफेशनल्स के लिए सॉफ्टवेयर प्रफेशनल्स की तरह मौकों की कोई कमी नहीं है। एंटी लेवल पर आप 25 से 35,000 रुपये महीने की जॉब पा सकते हैं। अनुभव और समय के साथ इसमें बढ़ोतरी होगी।



प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के विनायक मंदिर में की पूजा



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सरकार के मुखिया के तौर पर अपने 25 साल पूरे कर लिए। इस खास मौके पर उन्होंने दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना की। नरेंद्र मोदी का यह सफर 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के साथ शुरू हुआ था। इसके बाद 2014 में वह देश के प्रधानमंत्री बने और लगातार तीन बार इस पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री मोदी को 25 साल पूरे करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ‘प्रधान सेवक’ के रूप में मोदी की यात्रा ने समावेशी विकास की सोच को पूरे देश के मिशन में बदलने का काम किया है। इस सफर की दिशा ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ से तय हुई है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सरकार के मुखिया के तौर पर देश की सेवा के 25 साल पूरे करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।

राहुल और प्रियंका के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर



नईदिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तथा इंडिया गठबंधन के कई अन्य सांसदों के खिलाफ प्रार्थमिकी (एफआईआर) दर्ज की है। यह कार्रवाई मंगलवार को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान आकाशवाणी भवन परिसर में कथित तौर पर जबरन घुसने और धरना देने के मामले में की गई है। इस विरोध प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़ी मांगें भी शामिल थीं। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इंडिया ब्लॉक ने संसद भवन से निर्वाचन सदन (चुनाव आयोग का मुख्यालय) तक मार्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस मार्च के लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं मांगी गई थी और न ही दी गई थी। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को ईसीआई कार्यालय के पास रोका, तो विपक्ष के कई नेताओं ने धरना दिया।

राज्यसभा चुनाव से तय हुआ यूपी का नतीजा : सीएम योगी



लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव ने बता दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम होने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर ‘‘80-20’’ की लड़ाई शुरू हो गई है, जिसमें 80 प्रतिशत लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और 20 प्रतिशत पीडीए के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जीपीओ स्थित पटेल पार्क में आयोजित सेवा ज्योति यात्रा ‘विकसित भारत संकल्प सभा’ को संबोधित करते हुए योगी ने प्रधानमंत्री को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मंगलवार को उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव (नामांकन) से पता चल गया कि विधानसभा चुनाव का नतीजा क्या होने वाला है। 80-20 की लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। पीडीए का क्या हथ्र होगा, यह फिर से आपके सामने होगा।

मोदी के 25 साल गरीबों के कल्याण को समर्पित : शाह



गुरुग्राम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को नरेन्द्र मोदी के निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर 25 वर्ष पूरे करने की सराहना करते हुए इसे देश और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित यात्रा बताया। शाह ने यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सात अक्टूबर का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ‘‘स्वर्णिम और युगांतकारी’’ है। कार्यक्रम में शाह के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सेनी, केंद्रीय मंत्री एवं गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह और पार्टी की नवनियुक्त हरियाणा प्रभारी स्मृति ईरानी भी मौजूद थीं। शाह ने कहा कि मोदी के गुजरात और फिर केंद्र सरकार के प्रमुख के रूप में पच्चीस वर्ष देश के करोड़ों नागरिकों के कल्याण और भारत के गौरव के भी 25 वर्ष हैं। उन्होंने मोदी के दीर्घायु होने की कामना की। गृह मंत्री ने कहा, ‘‘हमने इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए देश के हर जिले में ‘सेवा ज्योति यात्रा’ आयोजित की है।’’ शाह ने, गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद संघर्षों से जूझते हुए आगे बढ़ने के लिए भी मोदी की सराहना की।

सिलचर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत

गुवाहाटी। सिलचर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पहले सिविक चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 42 में से 34 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की, जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सिलचर सिविक चुनाव बैलेट पेपर का इस्तेमाल करके कराए गए थे, जो विपक्षी पार्टियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। सिलचर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में एनडीए की शानदार जीत पर असम के मुख्यमंत्री ने कहा, अब कांग्रेस बैलेट पेपर से हुए चुनाव में भी हार गई है। असम के दूसरे सबसे बड़े शहर सिलचर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों में भाजपा और एनडीए की ज़बरदस्त जीत हुई है। उन्होंने आगे कहा कि सिलचर की जनता ने बैलेट पेपर से हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में हमें भारी बहुमत दिया है। यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतुत्व और विकसित भारत के लिए शहरी प्रशासन के उनके विज़न में लोगों के भरोसे को फिर से पक्का करती है। इस शानदार जनादेश के लिए मैं सिलचर की जनता के सामने सिर झुकाता हूँ और सिलचर को असम के प्रमुख शहरों में से एक बनाने के अपने वादे को दोहराता हूँ।

प्रशासनिक जीवन के 25 साल पूरे, प्रधानमंत्री बोले-

जनता का विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति रही

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रशासनिक जीवन में 25 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पीएम मोदी ने देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं को वरुंअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि सात अक्तूबर 2001 को जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब उन्होंने नहीं सोचा था कि एक दिन सार्वजनिक जीवन में यह पड़ाव भी आएगा।

उन्होंने कहा कि आज सरकार के प्रमुख के तौर पर देश की सेवा करते हुए 25 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने इसे जनता के लगातार मिल रहे आशीर्वाद का परिणाम बताया और भाजपा, एनडीए तथा लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोगों का आभार जताया।

पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने 140 करोड़ भारतवासियों के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि उनकी प्रार्थना है कि परमात्मा उन्हें इतनी शक्ति दें कि वह देश के लिए और अधिक ऊर्जा के साथ काम कर सकें और दिन-रात देशवासियों समेत सभी लोगों की सेवा कर सकें। पीएम मोदी ने कहा कि आज वह जो कुछ भी हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान जनता जनार्दन का है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनता जनार्दन उनके लिए ईश्वर का ही स्वरूप है। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों का विश्वास ही उनकी शक्ति रहा है। देश ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। इसलिए देश ही उनके लिए सबकुछ है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों का ही उनके ऊपर सबसे बड़ा हक है।

पीएम मोदी ने कहा कि 25 साल का जनविश्वास और 25 साल का अनुभव बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि यह पूंजी देश की है और मां भारती की हर संतान इसका अधिकारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्कूल के दिनों की याद करते हुए कहा कि सीखने की ललक उनके जीवन का हिस्सा बन गई और वह आज भी खुद को एक विश्वार्थी मानते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने ईश्वर से हमेशा यही मांगा कि सीखने की उनकी इच्छा कभी कम न हो।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि छोड़े मुड़कर देखने पर



उनके मन में कृतज्ञता का भाव आता है। हर घटना ने उन्हें कुछ न कुछ सिखाया। जिसने उन्हें गिराया, उसने खड़ा होना सिखाया और जिसने विरोध किया, उसने लोकतंत्र की शक्ति समझाई। हर संकट उनके धैर्य की परीक्षा रहा, जबकि हर सफलता ने बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने का समर्थन दिया।

पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान ने उन्हें असफलता से उठना सिखाया। कोरोना ने सामूहिक चेतना का पाठ पढ़ाया। मीडिया ने उन्हें खट्टे-मोटे अनुभवों से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि हर गांव और हर गरीब ने उन्हें सिखाया कि साधन-संसाधन भले ही सीमित हों, लेकिन सपने बड़े होने चाहिए और होसले बुलंद होने चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वेद से विवेकानंद तक जिस रात्र ने महान विचारों का अनुष्ठान किया है, जिस रात्र का अनुभव हजारों साल का है और जिसने मानव को मानवता का भरोसा दिलाया है, वहां उन्हें कभी नहीं लगा कि वह अकेले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम सेवक हैं, सेवा हमारा धर्म है और दीन-दुखियों की सेवा करना हमारा धर्म है।

पीएम मोदी ने कहा कि प्रशासनिक जीवन में उनकी यात्रा के हर पड़ाव पर साथ देने वाले प्रत्येक स्वयंसेवक और कार्यकर्ता को वह आदरपूर्वक नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन सिर्फ पुरानी यादों को ताजा करने का नहीं, बल्कि अपने संकल्पों को नई ऊर्जा देने का है। उन्होंने कहा कि यह उस वादे और इरादे को दोहराने का दिन है कि हम करके रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा, वी विल डू इट। वी विल डू इट। उन्होंने कहा कि लाल किले से उन्होंने ‘सबका प्रयास’ की बात की थी और भारत को नई बुलंदियों तक

पहुंचाने के लिए जरूरी जज्बा एक ही संदेश देता है— हम करके रहेंगे।

पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नारा लगवाया, %विकसित भारत बाय 2047, वी विल डू इट। तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी- वी विल डू इट। आत्मनिर्भर भारत- वी विल डू इट, ओलंपिक्स का आयोजन- वी विल डू इट, अंतरिक्ष में कदम- वी विल डू इट। उन्होंने कहा, ये ऊर्जा, ये आत्मविश्वास अद्भुत है। जहां ये बातें लहू बनकर दौड़ती हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। पीएम मोदी ने कहा कि 25 वर्षों की इस यात्रा को लोग उपलब्धि मानते हैं।

प्रधानमंत्री ने अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए कहा, मेरे काम संगठन का काम करने वाले का ही था। मैंने चुनाव लड़ाए थे, लेकिन एक भी चुनाव लड़ा नहीं था। चुनावी रजनीति में चमकने की चाहत होती तो बहुत पहले ही मैदान में उतर सकता था, लेकिन ये मेरा मिजाज नहीं था। मेरा क्या होगा, ये सोचा ही नहीं। बाल्यकाल से जो शिक्षा मिली, मैं एबीशन नहीं, मिशन के लिए जीने वाला इंसान रहा हूं।

पीएम मोदी ने कहा कि जीवन का एक ही ध्येय था, देश के लिए निस्वार्थ कर्म। मेरे लिए कर्म ही सबकुछ है। कर्म ही मेरा धर्म है। गीता ने हमें सिखाया है कर्मण्ये वाधिक्वरास्ते, मैं कर्म को अपना धर्म मानता हूं। हर कम पूरी क्षमता से करता रहूं% उन्होंने कहा, गीता ने ये भी है- निरंतर कर्म करो, बिना आसक्ति के कर्म करो, काम रकना नहीं चाहिए, प्रयास रकना नहीं चाहिए। इसलिए कर्म जिम्मेदारी नहीं, ये देश के प्रति मेरी साधना है। फल की कोई चिंता नहीं। परिस्थितियां बर्नी तो देशवासियों की सेवा का अविरल मौका मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने इस रात्र में जन्म लिया है, ये एहसास ही अमृत है। इसके सामने सत्ता सुख कुछ नहीं है। पद-प्रतिष्ठा तो कहीं भी मिल सकता है, लेकिन अब उस ट्रिब्यूनल के 19 जजों ने चुनाव आयोग के पोर्टल पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जजों का कहना है कि चुनाव आयोग का पोर्टल उसके काम में अड़ता डाल रहा है। जजों के मुताबिक पोर्टल में बहुत सारी

शेयर बाजार में भारी गिरावट सेंसेक्स 429 अंक टूटकर बंद

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में अचानक की गई बढ़ोतरी के कारण घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को भारी गिरावट देखी गई। इस फैसले से शेयर बाजार की पिछले दो दिनों से जारी तेजी पर ब्रेक लग गया। केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो रेट को 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 5.5 प्रतिशत करने और अपनी नीति को कैलिब्रेटेड टाइटनिंग में बदलने से निवेशकों की धारणा पर बुरा असर पड़ा। कारोबार के अंत में, बांम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 429.11 अंक (0.59%) की गिरावट के साथ 72,638.70 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 173.05 अंक (0.76%) फिसलकर 22,603.05 के स्तर पर आ गया। बाजार जानकारों के मुताबिक, निफ्टी इस समय अपने सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल 22,600 के ठीक पास बंद हुआ है।

आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.7% से 7.1% किया

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही, दूसरी और तीसरी तिमाही के ग्रोथ अनुमान भी बढ़ाए गए हैं। आरबीआई ने Q2FY27 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.4% से बढ़ाकर 7.2% और Q3FY27 के लिए 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। वहीं, Q4FY27 के लिए विकास दर का अनुमान 6.8% पर बरकरार रखा गया है। हालांकि, Q1FY28 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.3% से घटाकर 7.1% कर दिया गया है। मार्च 2027 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए नया जीडीपी ग्रोथ अनुमान पिछले अनुमान से 0.4 प्रतिशत अधिक है।

अमेरिकी कारोबारियों को मसालों पर शुल्क छूट की उम्मीद

वाशिंगटन। अमेरिका के मसाला कारोबारी भारत के साथ व्यापार समझौते के तहत भारतीय मसालों पर शुल्क से छूट मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि अमेरिकी उपभोक्ताओं को ये मसाले उचित कीमतों पर उपलब्ध होते रहें। अमेरिका हर साल भारत से करीब 70 करोड़ डॉलर मूल्य के मसालों का आयात करता है और आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच मसालों के व्यापार के अधिक बढ़ने की उम्मीद है। अमेरिकन स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन (ए.एस.टी.ए.) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सी.ई.ओ.) डोनाल्ड प्रैट ने कहा, हमें सरकार से मसालों पर शुल्क छूट का समर्थन जारी रखने की उम्मीद है। इसलिए हम आशा करते हैं कि दोनों देश मसालों की अमेरिका में आपूर्ति जारी रखने के लिए हरसंभव बेहतर कदम उठाएंगे। प्रैट ने कहा कि भारत, अमेरिका को मसालों की आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है।

आरबीआई ने बढ़ाया रेपो रेट एफडी वालों की बछे-बछे!

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी के तुरंत बाद फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) के निवेशकों के लिए बेहद शानदार खबर सामने आई है। देश की सबसे बड़ी और अग्रणी नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में 15 से 40 बेसिस पॉइंट्स (0.15% से 0.40%) तक की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। कंपनी द्वारा की गई यह बढ़ोतरी 7 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गई है। बजाज फाइनेंस में नया डिपॉजिट करने वाले रेगुलर डिपॉजिटर अब 31 से 60 महीने का निवेश के लिए सालाना 7.75% तक का ब्याज (क्वमुलेटिव आधार पर) पा सकते हैं, जो पहले सालाना 7.40% था। 12 से 17 महीने की अवधि के लिए ब्याज दरें सालाना 6.60% से बढ़कर 6.80% हो गई हैं।

आर्थिक/ताण्ड्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

प्रमुख समाचार

स्टेल प्रमुख समाचार

गौतम गंभीर ने अजीत अगरकर को दी भावुक विदाई



नई दिल्ली। अजीत अगरकर का सीनियर पुरुष चयन समिति के प्रमुख के तौर पर कार्यकाल समाप्त हो गया है। अगरकर अब आगे इस पद पर नहीं रहेंगे। अगरकर का कार्यकाल यादगार रहने के साथ ही विवादों में भी घिर रहा। अब भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने अगरकर को सराहा है। गंभीर का कहना है कि इतिहास अगरकर के प्रति ज्यादा उदार रहेगा।

अजीत अगरकर का मुख्य चयनकर्ता के रूप में कार्यकाल चार अक्तूबर को खत्म हो गया। अगरकर के साथ पिछले कुछ समय से गंभीर ने करीब से काम किया। अब जबकि अगरकर का कार्यकाल समाप्त हो गया है तो गंभीर ने सोशल मीडिया पर उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। गंभीर ने एक्स पर लिखा, प्रिय अजित भाई, आपके साथ काम करना मेरे लिए बेहद सौभाग्य की बात रही। वे तीन आईसीसी टूर्नामेंट आपके अटूट विश्वास का प्रमाण हैं। हमेशा टीम पहले और टीम सबसे ऊपर। मैं कहना चाहूंगा कि इतिहास आपके प्रति ज्यादा उदार रहेगा। हर चीज के लिए शुक्रिया। आपको भविष्य के लिए मेरी दिल से शुभकामनाएं।

अजीत अगरकर का भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के तौर पर कार्यकाल कई बड़ी उपलब्धियों से भरा रहा। हालांकि, इसी दौरान विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गजों के अंतरराष्ट्रीय करियर में भी बड़े बदलाव हुए। अगरकर के कार्यकाल को सिर्फ विवादों के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। उनके चयन पैनल के दौरान भारत ने तीन आईसीसी खिताब जीते। इनमें 2024 और 2026 के टी20 विश्व कप तथा 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी शामिल हैं। इसके अलावा भारत 2023 वनडे विश्व कप के फाइनल तक पहुंचा था। यानी अगरकर के नेतृत्व वाली चयन समिति के चुने स्कोड ने पिछले तीन वर्षों में चार आईसीसी सफेद गेंद टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई और तीन खिताब जीते।

अभिनय आकाश

देश में व्यापार को आसान बनाने और टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए सरकार जीएसटी 2.0 में बदलाव की तैयारी कर रही है। 8 अक्टूबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में ई-वे बिल के नियमों को ढीला करने, गिरफ्तारी के डर को खत्म करने और सालों से फंसे हजारों करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को जारी करने जैसे बड़े बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। जीएसटी काउंसिल बुधवार को होने वाली अपनी बैठक में कई ऐसे प्रस्तावों पर विचार करेगी, जिनमें ई-वे बिल की जरूरतों से जुड़े नियमों को आसान बनाना और जीएसटी कानून के तहत गिरफ्तार करने की शक्तियों को हटाना शामिल है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने ईटी को बताया कि ये प्रस्ताव टैक्सपेयर से जुड़े सभी पहलुओं – जैसे रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और रिफंड

से लेकर इनपुट टैक्स क्रेडिट और कानूनी विवाद – को कवर करते हैं। ये प्रस्ताव ज्यादा कागजी कार्रवाई वाले अनुपालन से हटकर ऑटोमेटेड, डेटा-आधारित और जोखिम-आधारित प्रशासन की ओर बढ़ने का संकेत देते हैं।

अगर जीएसटी काउंसिल इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है, तो गिरफ्तारी का फैसला अफसरों के हाथ में रहने के बजाय अदालत के अधीन हो जाएगा। वहीं, आपराधिक केस सिर्फ उन्हीं मामलों में दर्ज होंगे जो गंभीर और जानबूझकर की गई टैक्स चोरी से जुड़े होंगे। सबसे मुख्य प्रस्ताव इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को आसान बनाने से जुड़ा है। इससे कंपनियों को फंसी हुई पूंजी छूटेगी और उद्योग जगत को एक अप्रत्यक्ष बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावों में कई ऐसे व्यापारिक इनपुट्स पर भी क्रेडिट देने की बात कही गई है जो अब तक ब्लॉक रोककर रखे गए थे।



पिछले सितंबर में जीएसटी दरों के व्यापक युक्तिकरण के साथ इस बड़े सुधार की शुरुआत हुई थी, जिसने कारोबारियों और जीएसटी प्रणाली के बीच के तालमेल को पूरी तरह बदल दिया। इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को आसान बनाने का है, जिससे कंपनियों को फंसी हुई पूंजी मुक्त होगी और उद्योग जगत को एक अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलेगा। जीएसटी काउंसिल प्लॉट, मशीनरी और इनपुट सेवाओं पर चुकाए गए टैक्स को 5 वर्षों में मासिक किस्तों के रूप में वापस

(रिफंड) करने पर विचार करेगी। वर्तमान में कंपनियां आईटीसी के तहत इस पूरी रकम की भरपाई नहीं कर पाती थीं। पहले जिन व्यावसायिक इनपुट पर क्रेडिट ब्लॉक था, अब उसका दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव है। इनमें शामिल हैं— कर्मचारियों का स्वास्थ्य और जीवन बीमा। आउटडोर कैटरिंग। दूरसंचार (टेलीकॉम) टावर और कारखानों के बाहर बिछाई गई पाइपलाइन। नष्ट किए जाने वाले एक्सपायर्ड उत्पाद और कुछ मुफ्त नमूने। 13 सीटों तक के वाहन, उनका बीमा, रखरखाव और वाहनों की लीजिंग या हायरिंग।

5% टैक्स स्लैब में आने वाले कई उत्पाद (जैसे खाद्य पदार्थ, फार्मा, कपड़ा और इलेक्ट्रिक वाहन) इनवेंटड इयूटी स्ट्रक्चर (कच्चे माल पर ज्यादा टैक्स और तैयार माल पर कम टैक्स) का सामना कर रहे हैं। इसके कारण हजारों करोड़ रुपये का आईटीसी

अटका हुआ है। इस पूंजी के जारी होने से उद्योग इसे फिर से पूंजीगत व्यय के रूप में निवेश कर सकेंगे। टेलीकॉम टावरों और पाइपलाइनों पर क्रेडिट मिलने से दूरसंचार, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, उर्वरक, गैस वितरण और बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) क्षेत्रों के भारी खर्च में बड़ी राहत मिलेगी।

पहले यदि कोई स्प्लायर टैक्स जमा नहीं करता था, तो उसका खामियां वास्तविक खरीदार को अपना क्रेडिट गंवाकर भुगतान पड़ता था। यह जीएसटी में विवादों का सबसे बड़ा कारण रहा है। अब यदि सौदा वैध है, तो खरीदार को आईटीसी रखने की अनुमति दी जाएगी और टैक्स बचसूली सीधे डिफॉल्ट करने वाले स्प्लायर से की जाएगी। चूँकि अब इनवॉइस-टू-इनवॉइस मिलान से खरीदार और विक्रेता का डेटा जुड़ा हुआ है, इसलिए सिस्टम फर्जी या बेमेल क्रेडिट को उसके स्रोत पर ही पकड़ सकता है।

हजारों नागरिकों ने सेवा, संकल्प और जनभागीदारी के साथ दिया विकसित भारत-2047 का संदेश

सेवा संकल्प अभियान के तहत कबीरधाम में निकली भत्य सेवा ज्योति यात्रा

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक भावना बोहरा एवं फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन हुए शामिल

कवर्धा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज कबीरधाम जिले में भव्य सेवा ज्योति यात्रा निकाली गई। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा, पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा, फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष श्रीमती मोना सेन सहित जनप्रतिनिधियों और हजारों नागरिकों ने यात्रा में उत्साहपूर्वक सहभागिता की। सेवा ज्योति यात्रा से पूर्व शासकीय पीजी कॉलेज के डोम में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र



मोदी एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन के संबोधन को उपस्थित नागरिकों ने सुना। इसके बाद सेवा ज्योति यात्रा निर्धारित मार्ग से होते हुए सेवा ज्योति चौक पहुंची। यात्रा में सामाजिक संगठनों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों सहित बड़ी संख्या में जिलेवासियों ने भाग लेकर सेवा, जनभागीदारी और विकसित भारत-2047 के संकल्प का संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को श्री नरेंद्र

मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और आज 7 अक्टूबर 2026 को सरकार के मुखिया के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन 25 वर्षों की यात्रा सेवा, सुशासन, संकल्प और देश को आगे ले जाने की यात्रा रही है। श्री शर्मा ने कहा कि संकल्प लेना बड़ी बात है, लेकिन उसे धरातल पर उतारना उससे भी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत-2047 का संकल्प देश के सामने रखा है। वर्ष

2047 में जब भारत विकसित राष्ट्र बने, तब हमारा छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़, कबीरधाम विकसित कबीरधाम और कवर्धा विकसित कवर्धा बने, यह हम सभी का संकल्प होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लक्ष्य बड़ा हो सकता है और रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन संकल्प मजबूत हो तो मंजिल हासिल की जा सकती है। सेवा ज्योति यात्रा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि जिले के विकास, सेवा और जनभागीदारी का संकल्प है। जब संकल्प बड़ा हो, नीयत स्पष्ट हो और 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति साथ हो तो लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, हम जरूर करवें। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि पिछले वर्षों में देश ने राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। आतंकवाद के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों ने भारत के सामर्थ्य का संदेश दिया है।

जशपुर में हुई विकसित भारत संकल्प सभा

पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में निकली ‘सेवा ज्योति यात्रा’



जशपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा से राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जशपुर के रणजीता स्टेडियम में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल की उपस्थिति में आयोजित सभा में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी और सामूहिक प्रयास का संदेश दिया गया। संकल्प सभा के पश्चात पर्यटन मंत्रीराजेश अग्रवाल के नेतृत्व में रणजीता स्टेडियम से ‘सेवा ज्योति यात्रा’ निकाली गई। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, युवाओं और नागरिकों ने यात्रा में उत्साहपूर्वक सहभागिता की। राष्ट्रसेवा और विकसित भारत के संकल्प के साथ निकली इस यात्रा के माध्यम से नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने

और जनभागीदारी के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देने का संदेश दिया गया। सेवा ज्योति यात्रा रणजीता स्टेडियम से प्रारंभ होकर जयसंभ चौक होते हुए संगम चौक पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। यात्रा के दौरान विकसित भारत, राष्ट्रसेवा और सामूहिक सहभागिता का संदेश प्रमुखता से सामने आया। इसमें विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जुदेव,कृष्ण कुमार राय सहित जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, युवाओं और आम नागरिकों ने सहभागिता की। इस अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने

कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा और राष्ट्रसेवा की यात्रा के 25 वर्ष पूर्ण होना महत्वपूर्ण अवसर है। इन वर्षों में राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए देश के विकास और जनकल्याण को नई दिशा देने के निरंतर प्रयास हुए हैं। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य व्यापक जनभागीदारी से ही साकार होगा। सरकार के प्रयासों के साथ प्रत्येक नागरिक की सक्रिय सहभागिता, अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता और राष्ट्र के विकास में योगदान आवश्यक है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति सामूहिक प्रयास और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध विकसित भारत की मजबूत नींव हैं।

सेवा संकल्प अभियान भाजपा का फ्लॉप इवेंट : दीपक बैज

रायपुर। भाजपा के ‘सेवा संकल्प अभियान’ के नाम पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि अगर यह सेवा है, तो कर्मचारियों को धमकाकर भीड़ क्यों बुलानी पड़ रही है? सेवा बिना दबाव के होती है, तानाशाही से नहीं। भाजपा सरकार जिसे सेवा संकल्प अभियान कह रही है, वह वास्तव में सरकारी धन और प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर नरेंद्र मोदी की छवि चमकाने का इवेंट है। जमीनी हकीकत यह है कि न आम जनता की सुनवाई हो रही है और न ही जमीनी समस्याओं का समाधान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की साय सरकार ‘सेवा संकल्प’ के नाम पर प्रदेश की जनता के साथ धोखा कर रही है। यह कोई सेवा अभियान नहीं, बल्कि आरएसएस और भाजपा का फ्लॉप इवेंट है, जिसे चमकाने के लिए पूरी सरकारी



मशीनरी को झोंक दिया गया है। शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारियों और पंचायत सचिवों को जनसेवा के काम से हटाकर मोदी का गुणगान करने पर मजबूर किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जनता के पैसे की इस बर्बादी और प्रशासनिक तानाशाही का कड़ा विरोध करती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रशासनिक तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकारी अधिकारियों और निचले स्तर के कर्मचारियों को संघ और भाजपा के प्रचारक के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जनसेवा के बजाय कर्मचारियों को भीड़ जुटाने और इवेंट मैनेजमेंट के काम में धकेला जा रहा है। जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से मोदी जी की ब्रांडिंग करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। भाजपा सरकार ने सरकारी खजाने को अपना चुनावी फंड समझ लिया है।

यूसीसी पर महिलाओं ने रखी वेबाक राय



रायपुर। छत्तीसगढ़ महिला मंच और महाराष्ट्र मंडल महिला समिति की पदाधिकारियों व सदस्यों ने समान नागरिक संहिता समिति के समक्ष विवाह, विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील व व्यावहारिक विषयों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में यूसीसी समिति के सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एम.के. राऊत और वरिष्ठ अधिका का मोहन पवार ने महिलाओं द्वारा दिए गए सभी व्यावहारिक और कानूनी सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें उन पर विचार करने का पूर्ण आश्वासन दिया।

बहतराई की खेल भूमि ने देश को दिए कई प्रतिभावान खिलाड़ी : उपमुख्यमंत्री साव

पांच संभागों के 571 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

बिलासपुर। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने आज स्व. बी.आर. यादव राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, बहतराई में 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2026-27 का शुभारंभ किया। उन्होंने पांच संभागों से आए खिलाड़ियों के मार्च पास्ट की सलामी ली और गुब्बारे छोड़कर प्रतियोगिता का आगाज किया। बस्तर, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा और दुर्ग संभाग के 571 खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। उपमुख्यमंत्री श्री साव ने



खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बहतराई की खेल भूमि ने देश और प्रदेश को कई प्रतिभावान खिलाड़ी दिए हैं। इसी मैदान पर खेलकर संजु देवी ने एशियन गेम्स कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता, वहीं मधु सिदार और

गीता यादव ने अंडर-19 महिला हॉकी में देश को गौरवान्वित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संदेश ‘जो खेलेगा, वही खिलेगा’ का उल्लेख करते हुए खिलाड़ियों से पूरी खेल भावना और आत्मविश्वास के साथ श्रेष्ठ

प्रदर्शन करने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बहतरा विधायक श्री सुभांत शुक्ला ने कहा कि खेल के मैदान में कोई हारता नहीं है, खिलाड़ी या तो जीतता है या सीखता है। खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर संसाधन और सुविधाएं जरूरी हैं। उन्होंने बहतराई खेल परिसर को मध्य भारत के उत्कृष्ट खेल संस्थानों में विकसित करने के लिए इसके उन्नयन पर जोर दिया। पीएम श्री कन्या विद्यालय सरकंडा की छात्राओं ने भारत माता वंदना सहित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

दंतेवाड़ा में नवरात्रि की तैयारियां अंतिम चरण में

दंतेवाड़ा। जिले के मां दंतेश्वरी मंदिर में शारदीय नवरात्रि को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए प्रवेश और निकासी की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। मंदिर चौक से मंदिर परिसर तक सामान्य भक्त, व्हीआईपी और व्हीव्हीआईपी भक्तों के मंदिर में प्रवेश के लिए तीन अलग रास्ते होंगे। घी के दीये और चांदी के सिक्के की कीमत भी बढ़ी है। इस बार मंदिर के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर रोक रहेगी। मंदिर के बाहर मोबाइल जमा करने के लिए काउंटर बनाया जा रहा है। श्रद्धालु मोबाइल जमा करने के बाद ही मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश करेंगे। दंतेवाड़ा एसपी चंद्रमोहन सिंह ने भी मोबाइल को लेकर नई व्यवस्था की पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि इस व्यवस्था को लेकर बातचीत भी चल रही है। मंदिर समिति ओ मिल्ति जानकारी के अनुसार मंदिर में ज्योति कलश स्थापना के लिए घी के कलश की राशि इस बार 3100 रुपए रखी गई है। पिछली बार यह राशि 2100 रुपए थी। तेल के कलश की राशि 1100 रुपए ही रहेगी। मंदिर समिति के अनुसार इस बार करीब 10 हजार कलश स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।



भाजपा के राज में महिलाये डर के साये में जीने को मजबूर : कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश अपराध का गढ़ बन चुका है। बालोद में छात्रा पर एसिड अटैक की घटना इससे पहले दुर्ग जिले में कांवड यात्रा पर महिला पर एसिड अटैक की घटना ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं बताती हैं कि अपराधियों में कानून का भय खत्म हो गया है और भाजपा सरकार महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। एक घटना के बाद दूसरी घटना सामने आ रही है, लेकिन सरकार की ओर से केवल बयान और औपचारिक कार्रवाई दिखाई देती है। जब अपराधी खुलेआम महिलाओं और छात्राओं को निशाना बनाने का दुस्साहस कर रहे हैं, तो सरकार की पुलिसिंग और कानून का डर आखिर कहाँ है राज्य में महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। प्रदेश में हर दिन 8 महिलाएं दुराचार का शिकार हो रही हैं अर्थात् हर तीन घंटे में एक महिला के साथ बलात्कार की घटना हो रही है। महिलाओं को घर में घुसकर गोली मारी जा रही, राजधानी में गैंगरेप हो जाता है, एसिड अटैक हो रहा है।



तेलीबांधा चौक का नाम बदलने का कांग्रेस विरोध करती है

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा सेवा संकल्प अभियान के तहत रायपुर के प्रसिद्ध तेलीबांधा चौक समेत प्रदेश भर के 38 स्थानों का नाम सेवा ज्योति संकल्प चौक के नामकरण और बदलाव के फैसले का कांग्रेस कड़ा विरोध करती है। है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि तेलीबांधा चौक का नाम 100 वर्षों से भी अधिक पुराना है। ऐतिहासिक और सामाजिक पहचान को मिटाकर राजनीतिक नामकरण करना छत्तीसगढ़ की जनता और साहू समाज की भावनाओं के खिलाफ है। सरकार राज्य में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और विकास के असली मुद्दों पर काम करने के बजाय केवल स्थानों के नाम बदलकर प्रचार और इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि तेलीबांधा चौक की ऐतिहासिक पहचान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं दिया जाएगा और यदि इस फैसले को लागू करने की कोशिश की गई, तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के लोगों विशेषकर साहू समाज की भावनायें तेलीबांधा तालाब से जुड़ी हुई हैं।



आप के विरोध के डर से छात्रा दौरा रद्द किया ज्ञानेश कुमार ने

रायपुर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का प्रस्तावित छत्तीसगढ़ दौरा रद्द होने पर आम आदमी पार्टी ने तीखा हमला बोला है। पार्टी ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आम आदमी पार्टी के प्रबल विरोध और जनता के सवालों के डर से अपना दौरा रद्द करने पर मजबूर हुए हैं। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार ने अपने संवैधानिक पद की गरिमा का उल्लंघन किया है और निष्पक्षता की कसौटी पर पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। पद के दुरुपयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचाने के विरोध में आम आदमी पार्टी उनके तत्काल इस्तीफे की माँग करती है। उन्होंने कहा कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तब तक आम आदमी पार्टी उनकी गिरफ्तारी और इस्तीफे की माँग को लेकर अपना संघर्ष जारी रखेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर हर मंच तक उग्र आंदोलन और लड़ाई जारी रखेगी।



शिविर में 13,869 हितग्राहियों को मिला योजनाओं का लाभ

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में आम नागरिकों तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ ल। भ स ह ज त। से पहुँचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत बुधवार को बलोदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के लिए तिल्दा नगर स्थित बीएनबी स्कूल परिसर में विधानसभा स्तरीय सेवा संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। विभिन्न विभागों के माध्यम से कुल 13,869 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं से लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल थे तथा अध्यक्षता नगर पालिका तिल्दा की अध्यक्ष श्रीमती चंद्रकला खुमान वर्मा ने की। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य श्रीमती स्मृति वर्मा एवं श्रीमती शैल महेंद्र साहू, सांसद प्रतिनिधि श्री अनिल अग्रवाल सहित नगर पालिका के पार्षद एवं एलडरमैन, मंडल अध्यक्ष एवं सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंचगण तथा अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।



नवभारत फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन में शामिल हुए राज्यपाल

खेलों से मिलती है शारीरिक मजबूती और करियर की नई राह: डेका

बिलासपुर। राज्यपाल रमेन डेका नवभारत परिवार द्वारा आयोजित 17वीं अखिल भारतीय फुटबॉल एवं जिला स्तरीय विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने फाइनल मुकाबला देखा और विजेता तथा उपविजेता टीमों को ट्रॉफी एवं नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। अखिल भारतीय प्रतियोगिता के फाइनल में तमिलनाडु पुलिस ने दक्षीराजहरा माईस को 1-0 से हराकर खिताब जीता। विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में सेंट जेवियर्स स्कूल भरनी ने नवीन पिछड़ा वर्ग क्रीड़ा परिसर को पराजित कर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। राज्यपाल श्री डेका ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल शारीरिक मजबूती के साथ अनुशासन, टीमवर्क और



खेल भावना विकसित करते हैं। नियमित रूप से मैदान में खेलने से शारी स्वस्थ और सक्रिय रहता है। उन्होंने कहा कि खेल अब करियर का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर आगे बढ़ने के अवसर बढ़े हैं। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में

खिलाड़ियों की सहभागिता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ के खेलों के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दीं। श्री डेका ने कहा कि फुटबॉल हमें सिखाता है कि लक्ष्य पाने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी भूमिका निभानी होती

है। एक-दूसरे का साथ देना, नियमों का सम्मान करना और अंतिम मिनट तक प्रयास करते रहना ऐसे गुण हैं, जो जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी होते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि खेल का आनंद लें, मेहनत करते रहें और हार से सीखकर फिर मैदान में उतरें। आपकी लगन ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। राज्यपाल ने कहा कि विद्यालय स्तर की प्रतियोगिताएं बच्चों की प्रतिभा निखारने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इन्हीं बच्चों में से खिलाड़ी आगे चलकर राज्य और देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जिला और राज्य स्तर के मुकाबलों से अनुभव मिलता है, जबकि अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में विभिन्न राज्यों की टीमों के साथ खेलने से खेल का स्तर बेहतर होता है और आगे की तैयारी की दिशा मिलती है।

बस्तर ओलंपिक 2026 वन मंत्री केदार कश्यप ने कराया पंजीयन

जगदलपुर। जगदलपुर के धरमपुरा स्थित खेल परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वन मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर ओलंपिक 2026 के लिए स्वयं अपना पंजीयन कराया और बस्तर ओलंपिक के शुभंकर के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाई। उन्होंने इस आयोजन को बस्तर की खेल प्रतिभाओं के लिए एक बहुत बड़ा और सुनहरा मंच बताया। इस अवसर पर वन मंत्री ने युवाओं, महिलाओं और सभी खेल प्रेमियों से बड़-चढ़कर पंजीयन कराने की अपील की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में 3 लाख 91 हजार 289 खिलाड़ियों ने इसमें पंजीयन कराया था, और



इस बार इसका दोगुना पंजीयन करने का लक्ष्य रखा गया है। वन मंत्री ने कहा कि बस्तर ओलंपिक सुदूर अंचल की छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें बड़ा मंच प्रदान करने का एक बेहतरीन माध्यम है। जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से अधिक से अधिक खिलाड़ियों को

जोड़ने की अपील करते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में नये बस्तर की एक नई पहचान उसके प्रतिभाशाली युवाओं के दम पर बनेगी। इस कार्यक्रम के दौरान चित्रकोट विधायक विनायक गोयल सहित क्षेत्र के कई गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित रहे।